

मोदी बोले- झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्च विपक्षियों को लग रही:

कहा:4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन होगा; टीएमसी की हार ही भय की हार है

कोलकाता, एजेंसी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बंगाल के मथुरापुर और कृष्णानगर में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा- जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। TMC हारेगी और भाजपा का भरोसा जीतेगा। मोदी ने कहा कि बंगाल की धरती मां दुर्गा को पूजती है, लेकिन TMC ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोटिंग की। TMC की सरकार में गुंडों और बलात्कारियों को खुला संरक्षण मिला हुआ है। बंगाल की बेटियां ये अत्याचार कभी नहीं भूल सकतीं।

चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी खाने पर उन्होंने कहा- झालमुड़ी मैंने खाई है पर मिर्च विपक्ष को लग रही है। अब का मतदान सभी पुराने



पीएम ने कहा- TMC को अपने हितों की चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल की निर्मम सरकार को सिर्फ अपने हितों की चिंता है, उसे आपके सुख-दुख से कोई लेना-देना नहीं है। इसका एक उदाहरण है, मथुरापुर का भंग मेला... भंग मेले को राज्य सरकार से वह समर्थन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था।

बोले- सभी दल महिला विरोधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि TMC और इन सारे दलों का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। कुछ दिन पहले संसद में जो कुछ हुआ आपने देखा है। भाजपा सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव लेकर संसद में आई थी लेकिन TMC ने इसके खिलाफ वोटिंग की। उन्होंने बंगाल की माताओं का अधिकार छीना। TMC ने यहां महिलाओं के सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है उसका हिसाब आपका वोट करेगा।

रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं यहां परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। पीएम मोदी एक दुकान पर रुके और झालमुड़ी रविवार को पश्चिम बंगाल के

झाड़ग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान एक दुकान पर रुके और झालमुड़ी खाई थी।

जयपुर में एक साल तक किराए पर रहा आतंकी:

सिर्फ नमाज के लिए बाहर निकलता था, हरियाणा के युवक ने दिलाया था कमरा



जयपुर, एजेंसी। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी उमर हारिस (अमजद) उर्फ खरगोश जयपुर के दिल्ली रोड स्थित जयसिंहपुरा खोर इलाके में करीब एक साल तक रहा। उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट भी बनवा लिया था। इसी पासपोर्ट से आतंकी इंडोनेशिया और फिर सऊदी अरब भागने में भी सफल रहा।

राजस्थान एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच में सामने आया कि उमर हारिस सड़वा मोड़ के पास राशिद विहार कॉलोनी में 'सज्जाद' नाम से रह रहा था। उसे यहां 1500 रुपए में किराए का कमरा हरियाणा के युवक ने दिलवाया था।

स्थानीय लोगों के अनुसार, वह दिन के करीब 16 घंटे लैपटॉप पर बिताता था। वह किसी से बात नहीं करता था।

लोगों से उसका संपर्क न के बराबर था। वह केवल नमाज के लिए मस्जिद जाता और तुरंत लौट आता था। उसकी इस चुप्पी और दूरी ने ही उसे एक साल तक पूरी तरह गुमनाम बनाए रखा। आसपास रहने वाले लोगों को भी उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी।

बीकाजी के CMD शिवरतन अग्रवाल का हार्ट अटैक से निधन :

चेन्नई में ली अंतिम सांस, पत्नी के ऑपरेशन के लिए परिवार के साथ गए थे



बीकानेर, एजेंसी। बीकाजी के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल (74) का गुरुवार सुबह चेन्नई में निधन हो गया। वे अपनी पत्नी के ऑपरेशन के सिलसिले में चेन्नई में थे।

गुरुवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार, उनकी पत्नी का हाल ही में हार्ट बायपास का ऑपरेशन हुआ था।

डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी। इसी कारण शिवरतन अग्रवाल परिवार सहित वहां के एक होटल में ठहरे हुए थे। बीकानेर के सार्दुलगंज के रहने वाले शिवरतन 10 दिन पहले परिवार के साथ चेन्नई गए थे। गुरुवार सुबह करीब साढ़े सात बजे शिवरतन अग्रवाल कुछ असहज महसूस कर रहे थे। हालात बिगड़ने पर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया था। जहां उनका निधन हो गया।

149 दिन बाद खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट

सीएम के बाद शंकराचार्य ने किए दर्शन, भगवान ने दिए मौसम अनुकूल रहने के संकेत



चमोली, एजेंसी। चारधाम यात्रा के पांचवें दिन चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं। सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर मंदिर के द्वार खुलते ही सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भगवान के दर्शन किए। अनुमान है कि करीब 7 हजार



उत्तियाल ने बताया कि इस साल कंबल धी में लंबालव मिला है, जो ये संकेत देता है कि पूरे साल मौसम अनुकूल रहेगा।

अब चारों धामों के कपाट खुल चुके: बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही अब श्रद्धालु उत्तराखंड में स्थित चारों धामों के दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले अक्षय्य तृतीया के मौके पर 19 अप्रैल

बंगाल के कुमारगंज में भाजपा प्रत्याशी को दौड़ाकर पीटा

आसनसोल में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा की कार पर हमला; मुर्शिदाबाद में ममता-हुमायूं कबीर समर्थक

कोलकाता/चेन्नई, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से भाजपा कैडिडेट सुबेंद्रु सरकार पर हमला हुआ है। सुबेंद्रु हमले से बचने के लिए भाग रहे दिखे। उनका सिक्किमिटी गार्ड उनके साथ है। इसके बावजूद भी सुबेंद्रु को पीटती है।

इधर, बर्नपुर के रहमतनगर इलाके में आसनसोल साउथ सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर भी हमला हुआ। इससे गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। अग्निमित्रा ने बताया कि एक मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय उनकी कार पर पत्थर फेंके गए।

अग्निमित्रा ने हीरापुर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई है। बंगाल में कई अन्य जगहों पर BJP और TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं। कई जगह EVM खराब होने की शिकायत भी आई है।



नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग का इस्तीफा:

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी से संबंधों पर विवाद

एक महीने में दो मंत्री सरकार से बाहर

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और कारोबारी दीपक भट्ट से संबंध का आरोप है। इसके अलावा निवेश और वित्तीय लेनदेन को लेकर भी सवाल उठे हैं। नेपाल के अखबार कांतिपुर की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने निष्पक्ष जांच और हितों के टकराव से बचने के लिए पद छोड़ने की बात कही।

गुरुंग ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 'मैंने अपने खिलाफ उठे सवालों को गंभीरता से लिया है। मेरे लिए



नैतिकता किसी भी पद से बड़ी है और जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत है।' यह नेपाल की नई सरकार में एक महीने के भीतर दूसरा मामला है, जब

किसी मंत्री को पद छोड़ना पड़ा है। इससे पहले 9 अप्रैल को श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीपक कुमार साह को अनुशासनहीनता के आरोप में हटाया गया था।

दीपक भट्ट की गिरफ्तारी के बाद गुरुंग पर सवाल उठे

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुंग के कारोबारी दीपक भट्ट से संबंधों को लेकर विवाद हुआ। दीपक भट्ट को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच जारी है। भट्ट की गिरफ्तारी

के बाद गुरुंग की वित्तीय गतिविधियों, निवेश और शेयर को लेकर सवाल उठने लगे थे। मीडिया में उनके कथित संबंध और असामान्य ट्रांजेक्शन पर लगातार रिपोर्ट्स आईं।

कांतिपुर को मिले बैंक रिकॉर्ड के अनुसार, गुरुंग के निजी खाते, उनकी संस्था 'हामी नेपाल' और कंपनियों के बीच बड़े पैमाने पर लेनदेन हुए। इनमें कई ट्रांजेक्शन ऐसे हैं, जिनका सोर्स और उद्देश्य साफ नहीं हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि 'हामी नेपाल' के खाते हिमालयन बैंक और नबिल बैंक में थे।

सबरीमाला केस, जस्टिस नागरत्ना बोलीं-वॉट्सएप यूनिवर्सिटी से जानकारी नहीं



● थरूर के आर्टिकल के जिक्र पर सीजेआई ने कहा- लेख पर्सनल ओपिनियन

नई दिल्ली, एजेंसी। केरलम के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि वॉट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी दाउदी बोहरा समुदाय की ओर से पेश हुए सोनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल की दलील के जवाब में की थी। कौल ने कहा था कि ज्ञान और समझ, चाहे वह किसी भी सोर्स से मिली हो, उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। कौल एक अखबार में कांग्रेस सांसद डॉ. शशि थरूर के लिखे लेख का हवाला दे रहे थे।

अनुच्छेद 26 में धर्म से जुड़े मामलों का मैनेजमेंट संभालने का अधिकार शामिल एडवोकेट कुमार: अब, यदि कोई अनुच्छेद 26 को बारीकी से देखे, तो उसमें साफ-साफ इंफ्रस्ट्रक्चर का एक अंतर दिखाई देता है। खंड (a) और (b) धार्मिक पहलुओं से जुड़े हैं। इनमें धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं बनाना, उनका रखरखाव और धर्म से जुड़े मामलों में अपने कार्यों का मैनेजमेंट संभालने का अधिकार शामिल है। खंड (c) और (d) संपत्ति से जुड़े हैं। इनमें संपत्ति का स्वाभिमत्त्व रखने और उसे अर्जित करने, कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार शामिल है। ये आपस में जुड़े हुए हैं और सेवयुलर क्षेत्र से संबंधित हैं। यह फर्क जानबूझकर किया गया है। संविधान निर्माताओं का इरादा यह था कि जहां खंड (a) और (b) के तहत धार्मिक मामले केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन सुरक्षित हैं, वहीं खंड (c) और (d) के तहत धर्मनिरपेक्ष पहलुओं का संचालन कानून के अनुसार किया जाएगा।

कोई नहीं बचा; शवों को पहचानना मुश्किल

मिर्जापुर में हादसा: 11 की मौत, बोलेरो में 9 जिंदा जले

बेटे का मुंडन कराकर लौट रहा था परिवार

मिर्जापुर, एजेंसी। यूपी के मिर्जापुर में बुधवार रात सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। इसमें बोलेरो सवार 9 लोग जिंदा जल गए। हादसा रात 9.30 बजे मिर्जापुर-रीवा नेशनल हाईवे पर हुआ। पुलिस के मुताबिक, एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक ब्रेक फेल होने से बेकाबू हो गया। ट्रक ने आगे चल रही बोलेरो और स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियां आगे चल रहे एक ट्रॉले से जा टकरा गईं।

रफ्तार तेज होने की वजह से ट्रक के बाद बोलेरो उछलकर अलग हो गई। तेज धमाके के साथ उसमें आग लग गई। जबकि, स्विफ्ट कार ट्रक और ट्रॉले के बीच फंसे गई। आग इतनी भीषण थी कि



बोलेरो सवार 9 लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। इसमें एक ही परिवार के 8 लोग और एक ड्राइवर था। करीब ढाई घंटे तक बोलेरो धू-धू कर जलती रही। मौके पर चीख



पुकार मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए आए, लेकिन आग तेज होने की वजह से कोई पास नहीं जा पाया।

लोग अंदर ही फंसे रहे। बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड की

ट्रम्प ने भारत को नरक का द्वार बताया:

कहा- भारतीय अमेरिका में बच्चों को जन्म देकर नागरिकता लेते हैं, फिर परिवार बुलाते हैं

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और चीन को हेल होल (नरक का द्वार) बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी पोस्ट की है, जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने की आलोचना करके भारत-चीन समेत कई देशों पर विवादित टिप्पणी की गई है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि उन्हें अदालतों और कानूनी संस्थाओं पर भरोसा नहीं है कि वे इस मुद्दे पर सही फैसला लें।

ट्रम्प बोले- कैलिफोर्निया में भारत-चीन का दबदबा: ट्रम्प



ने चिट्ठी में कैलिफोर्निया के टेक सेक्टर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाई-टेक नौकरियों में भारत और चीन के लोगों का बहुत ज्यादा असर है। उनके मुताबिक, वहां की कंपनियों में भर्ती का माहौल ऐसा बन गया है कि बाकी लोगों के लिए मौके बहुत कम रह गए हैं।

फ्लैट में पुलिस की छापामार कार्रवाई से मची भगदड़, गाजियाबाद में देह व्यापार का भंडाफोड़



साहिबाबाद, एजेंसी। टीला मोड़ थाना पुलिस ने तुलसी निकेतन स्थित एक फ्लैट में संचालित देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने महिला संचालिका समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 21 अप्रैल की रात छपेमारी कर चार युवतियों को रेस्क्यू किया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रात मुखबिर ने तुलसी निकेतन कालोनी में प्रथम तल स्थित एक फ्लैट में देह व्यापार संचालित होने की सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने छपेमारी की। छापेमारी के दौरान एक महिला और व्यक्ति आपत्ति जनक स्थिति में मिले। फ्लैट में चार अन्य युवतियां भी थीं। जिन्हें रुपयों का लालच देकर बुलाया गया था। पुलिस ने देह व्यापार को संचालित करने वाली एक महिला, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर संबंधित कार्रवाई की जा रही है। युवतियों को उनके स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

सिर पर चोट या हार्ट अटैक... 30 वर्षीय एक्ट्रेस

दिव्यांका सिरोही की कैसे हुई मौत



गाजियाबाद, एजेंसी। राजनगर एक्सप्रेसशन की सोसायटी में रहने वाली हरियाणवी अदाकारा दिव्यांका सिरोही का 30 वर्ष की उम्र में मंगलवार देर रात को निधन हो गया। वह घर पर अचानक चक्कर आने के बाद गिर गई। जिससे उन्हें चोट भी लग गई। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। हालांकि मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। बुधवार को परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। मूल रूप से बुलंदशहर निवासी दिव्यांका सिरोही ने मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीसीए की पढ़ाई की थी। सिक्किम से एमबीए की डिग्री हासिल की। वर्तमान में वह गाजियाबाद की सोसायटी में रहती थी। उन्होंने सुनंद शर्मा के मशहूर गाने मेरी मम्मी नू पसंद नी तू पर एक वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

50 से ज्यादा हरियाणवी गानों में किया काम : इस वीडियो को दो करोड़ व्यूज मिले थे। इसके बाद उन्हें हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। दिव्यांका 50 से ज्यादा हरियाणवी गानों में काम किया। उन्होंने मासूम शर्मा के साथ कई गानों में काम किया। मंगलवार देर रात उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह चक्कर खाकर फर्श पर गिर गई। जिसमें उनके सिर पर गहरी चोट लगी। स्वजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दिव्यांका की मौत के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में कोई शिकायत भी नहीं दी गई है।

देशभर में हैं लाखों प्रशंसक: दिव्यांका ने सिरसा के जेसीडी में लाइव शो में सिंगर मासूम शर्मा के साथ मंच साझा किया था। यहां उन्हें उन्हें नई पहचान मिली थी। जिसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। अभिनय में कदम रखने से पहले वह नौकरी करती थीं। उन्होंने अभी शादी नहीं की थी। उनके निधन पर हरियाणवी कलाकारों में शोक की लहर है। हरियाणवी कलाकार मजीत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। देशभर में उनके प्रशंसक थे। इंस्टाग्राम पर 13 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं।

11 साल बाद पुलिस के हत्ये चढ़ा शांति लुटेरा,

बोलैरो लूट की वारदात को दिया था अंजाम



दौसा, एजेंसी। कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिछले 11 वर्षों से फरार चल रहे शांति अपराधी वहीद खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने साल 2015 में अपने साथियों के साथ मिलकर एक बोलैरो गाड़ी और कीमती सामान लूटने की वारदात को अंजाम दिया था और तब से ही पुलिस को चकमा दे रहा था। वारदात की कदावी : मानवता का फायदा उठाकर की थी लूट कोतवाली प्रभारी भगवान सहाय शर्मा ने बताया कि यह मामला 12 अप्रैल 2015 का है। पीडित शिवराम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि:

दौसा बस स्टैंड पर आरोपियों ने ‘मरीज के साथ होने’ का हवाला देकर मानवता के आधार पर बोलैरो गाड़ी रुकवाई।

रामगढ़ पहुंचने पर आरोपियों ने गाड़ी आगे ले जाने का दबाव बनाया :। रास्ते में एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई, जिसमें से 4-5 लोग उतरे। बदमाशों ने चालक फैलीराम और राधेश्याम पर कट्टा तान दिया, उनके हाथ-पांव बांधे और जंगल में फेंककर बोलैरो लेकर फरार हो गए। लुटेरों ने चांदी की चंल, 3,500 रुपये और तीन मोबाइल भी छीन लिए। जाते-जाते आरोपियों ने सिम निकालकर चालक की जेब में 200 रुपये ‘खचों’ भी डाल दिया था।

पहचान छिपाकर काट रहा था फरारी : घटना के बाद से ही वहीद खान लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। वह मुख्य रूप से झाड़वी का काम करने लगा और यूपी, दिल्ली, हरियाणा और हैदराबाद जैसे राज्यों में टूक के जरिए पाउडर और मार्बल सप्लाई करने लगा, ताकि पुलिस की नजरों से बचा रहे।

पकड़ा गया ‘मैकेनिक’ बना लुटेरा : पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि आरोपी वहीद खान (पुत्र आसमोहम्मद उर्फ आसु) अब सीकरी गांव में अपनी पहचान छिपाकर मोटर साइकिल सुधारने (मैकेनिक) का काम करने लगा है। इस सटीक सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाया और 11 साल से फरार चल रहे इस इनामी अपराधी (निवासी तेसकी, थाना सीकरी, जिला डींग) को दबोच लिया।

दिल्ली में डायबिटीज के मरीजों और अस्पतालों को चेतावनी, नकली ‘माउनजारो’ इंजेक्शन के खतरे पर एडवाइजरी जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। गुरुग्राम में नकली ‘माउनजारो’ इंजेक्शन के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में भी हड़कप मच गया है। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि इन इंजेक्शनों की सप्लाई दिल्ली के थोक दवा बाजार से जुड़ी हो सकती है। इसे लेकर दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। विभाग ने मरीजों और अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए ड्राग निरीक्षकों को थोक बाजारों और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नकली इंजेक्शनों के दिल्ली कनेक्शन की पड़ताल के लिए विभाग ने संदिग्ध आपूर्तिकर्ताओं की पहचान व खोज अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही थोक विक्रेताओं को अपने स्टॉक का मिलान अधिकृत कंपनी के बिल (जीएसटी बिल) से करने को कहा गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी तुरंत



पकड़ में आ सके।

लोगों की जान से जुड़ा है मामला, सिर्फ धोखाधड़ी नहीं: विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह मामला केवल आर्थिक धोखाधड़ी नहीं, बल्कि लोगों की जान से जुड़ा गंभीर खतरा है। माउनजारो जैसे इंजेक्शन को दो से आठ डिग्री सेल्सियस के बीच सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है, जबकि नकली नेटवर्क में इसे सामान्य तापमान पर रखा जा रहा था। इससे दवा

की गुणवत्ता प्रभावित होकर यह जहरीली भी हो सकती है। बिना वैध लाइसेंस या सटीक दस्तावेजों के ऐसे इंजेक्शन बेचने वालों के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

किस काम में आता है माउनजोरो इंजेक्शन: माउनजारो (टिरजेपटाइड) का उपयोग मुख्य रूप से टाइप-टू डायबिटीज

के मरीजों में रक्त शर्करा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह इंसुलिन के प्रभाव को बेहतर बनाता है और भूख कम कर वजन घटाने में भी सहायक होता है। हाल में इसका उपयोग मोटापा प्रबंधन में भी चिकित्सकीय निगरानी में किया जा रहा

है।

इन बातों का मरीज रखें ख्याल: भारी छूट सबसे बड़ा संकेत: माउनजारो पर सामान्यतः 10 प्रतिशत तक ही छूट मिलती है। 25-30 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव मिलने पर सतर्क हो जाएं।

पैकेजिंग की जांच करें:

पैकेट पर छापाई, फांट और स्पेलिंग में गड़बड़ी नकली का संकेत हो सकती है। बैच नंबर और एक्सपायरी डॉक्स व पेन (इंजेक्शन) पर एक समान होने चाहिए।

इंजेक्शन पेन की गुणवत्ता: असली पेन स्मूथ होता है और उसका लाक सिस्टम सही ढंग से काम करता है। नकली में लीकेज या खराब प्लास्टिक की समस्या हो सकती है।

कहां से खरीदें:

ऑनलाइन या अनजान विक्रेता से खरीदने से बचें। केवल अधिकृत भंडारक या अस्पताल की फार्मसी से ही दवा लें। बिना पक्के जीएसटी बिल के दवा न खरीदें। बिल पर औषधि लाइसेंस नंबर जरूर जांचें। क्यूआर कोड या बारकोड स्कैन कर सत्यापन करें। इंजेक्शन इस्तेमाल से पहले डॉक्टर को जरूर दिखाएं।

गुरुग्राम में वाहन की टक्कर से नाले में गिरा 12वीं का छात्र, मौत

सोहना, एजेंसी। रायसीना गांव के समीप हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से छात्र सड़क किनारे बने नाले में जा गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं, टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश जारी है।मृतक की पहचान रायसीना निवासी विनीत के रूप में हुई है। विनीत अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी दो बहनें हैं। बताया जा रहा है कि उसने हाल ही में 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया था और पढ़ाई में भी अच्छे छात्र था। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार, विनीत मोटरसाइकिल से सोहना ढाणी की ओर कुछ सामान लेने जा रहा था। गांव से कुछ दूरी पर पहुंचते ही एक अज्ञात वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क किनारे बने नाले में जा गिरा। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे।



‘कमांड सेंटर’ के जरिये प्रदूषण पर कसी जाएगी नकेल

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के शास्त्री पार्क स्थित आईटी पार्क में एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) स्थापित किया जा रहा है। यह सेंटर शहर में वायु प्रदूषण के स्तर की ‘रियल-टाइम’ निगरानी करेगा। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना है। इस सेंटर की मदद से अधिकारी न केवल हवा की गुणवत्ता पर नजर रख सकेंगे, बल्कि यमुना के पानी की स्थिति की भी निगरानी की जाएगी। केंद्र में ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग



करके डेटा का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना और उन्हें रोकना आसान होगा। अभी तक सरकार केवल सर्दियों के लिए अस्थाई तौर पर दिल्ली सचिवालय में ‘ग्रीन वार रूम’ बनाती रही है, लेकिन यह सेंटर एक स्थाई ढांचा होगा। अधिकारियों के अनुसार यह सेंटर 300 करोड़ के व्यापक प्रदूषण नियंत्रण बजट का हिस्सा है। इसके जरिए न केवल

हवा बल्कि यमुना के पानी और

सड़कों पर तैनात मशीनीकृत सफाई वाहनों की भी निगरानी होगी, जिससे जवाबदेही तय की जा सकेगी।

कैसे काम करेगा यह

सिस्टम: यह कमांड सेंटर विभिन्न स्रोतों से डेटा को एक ही छत के नीचे लाएगा।

शिकायतें : ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप और एम्सीडी के 311 ऐप से आने वाली शिकायतों का

एक ही जगह पंजीकरण होगा।

डेटा एकीकरण : डस्ट पोर्टल, उद्योगों की चिमनियां से निकलने वाले धुएँ की निगरानी प्रणाली और दिल्ली के 46 एयर क्वालिटी स्टेशनों का डेटा भी यहीं एकीकृत होगा।

जमीनी स्तर पर कार्रवाई :

शिकायतों के मिलते ही निकटतम टीम या ‘वायु रक्षक’ को तुरंत मौके पर भेजा जाएगा ताकि समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस सेंटर को आगामी सर्दियों से पहले पूरी तरह सक्रिय करना है। इस हाई-टेक पहल से उम्मीद है कि राजधानी में धूल, औद्योगिक धुएँ और अन्य प्रदूषण कारकों पर भी बेहतर तरीके से लगाम लगाई जा सकेगी।

ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन ने अचानक छोड़ा पद

वॉशिंगटन, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पेंटागन ने बुधवार को अचानक घोषणा की कि नौसेना सचिव जॉन फेलन अपना पद छोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किसी सैन्य सेवा के प्रमुख का यह पहला इस्तीफा है। हालांकि, रक्षा विभाग में पिछले कुछ समय से कई बड़े अधिकारियों को हटया जा रहा है। फेलन के अचानक हटने का कोई कारण नहीं बताया गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है और दुनिया भर में तेह्रान से जुड़े जहाजों को निशाना बना रही है। अब ट्रंप के करीबी और अंडरसेक्रटरी हंग काओ नौसेना के कार्यवाहक सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। काओ नौसेना में 25 साल तक रहे हैं और उनके पास युद्ध का अनुभव भी है। फेलन का



पद से हटना पेंटागन के शीर्ष नेतृत्व में फेरबदल की एक लंबी कड़ी का हिस्सा हो सकता है। कुछ हफ्ते पहले ही रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया था। हेगसेथ ने पिछले साल पद संभालने के बाद से कई जनरलों और एडमिरलों को हटाया है। इनमें एडमिरल लीसा फ्रेंचेत्ती और जनरल जिम स्लाइफ भी शामिल हैं। ट्रंप ने जनरल चार्ल्स सीव्यू ब्राउन जूनियर को भी उनके पद से हटा दिया है। फेलन का इस्तीफा बहुत चौकाने वाला है। उन्होंने मंगलवार को ही वॉशिंगटन में नौसेना के एक सम्मेलन में

हिस्सा लिया था। वहां उन्होंने पत्रकारों से अपने एजेंडे पर बात की थी। उन्होंने सांसदों के साथ बजट और नए जहाज बनाने की कोशिशों पर भी चर्चा की थी। हालांकि, पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बताया कि फेलन तुरंत अपना पद छोड़ रहे हैं। बता दें कि फेलन ने पहले कभी सेना में काम नहीं किया था। उन्हें नौसेना में बड़े बदलाव करने के लिए लाया गया था। वे एक निजी निवेश कंपनी के संस्थापक भी रहे हैं। फेलन ऐसे समय में जा रहे हैं जब नौसेना बहुत व्यस्त है। उसके तीन विमानवाहक पोत मध्य पूर्व में तैनात हैं। साथ ही नौसेना कैरिबियन में ड्रम के खिलाफ अभियान चला रही है। जनवरी में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने में भी नौसेना का अहम भूमिका थी। नए कार्यवाहक सचिव हंग काओ वियतनाम से आए शरणार्थी हैं।

रोम में भारतीय दूतावास ने लगे आरोपों को बताया झूठा और मनगढ़ंत, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई

रोम, एजेंसी। इटली की राजधानी रोम में स्थित भारतीय दूतावास ने एक भारतीय नागरिक द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को सिरि से खारिज कर दिया है। दूतावास ने बुधवार को एक सख्त स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि वायरल वीडियो में किए गए सभी दावे पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं। दूतावास की ओर से यह प्रतिक्रिया तब आई जब उस व्यक्ति ने राजनयिक मिशन पर मदद न देने और दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए, जिससे डिजिटल दुनिया में काफी हलचल मच गई थी। रोम स्थित भारतीय दूतावास ने इस पूरे विवाद की असलियत बताते हुए कहा कि वह व्यक्ति मदद मांगने के बहाने दूतावास के परिसर में आया था। लेकिन जब सुरक्षाकर्मियों ने उससे मानक सुरक्षा नियमों के तहत उसकी पहचान पूछी, तो उसने सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाक्स पर दूतावास ने जानकारी दी कि वे उस व्यक्ति से मिलने के लिए पूरी तरह

रोम में भारतीय दूतावास विवाद



तैयार थे, लेकिन उसने अपनी पहचान या पासपोर्ट दिखाने से मना कर दिया। किसी भी देश के दूतावास में प्रवेश के लिए कुछ बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने जानबूझकर नियमों को तोड़ा।

व्यक्ति ने दूतावास पर क्या आरोप लगाए थे: सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में भारतीय मूल के व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि रोम में दूतावास के

लिए गलत तथ्यों के साथ वीडियो साझा किया।

सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन क्यों है जरूरी: दूतावास ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि सुरक्षा प्रक्रियाएँ रूटीन का हिस्सा हैं और विदेशों में किसी भी राजनयिक मिशन की सुरक्षा और कामकाज के लिए बेहद जरूरी हैं। बिना पहचान पत्र देकर किसी भी अनजान व्यक्ति को संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देना जोखिम भरा हो सकता है। दूतावास ने यह भी साफ किया कि स्टाफ ने किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया, बल्कि केवल अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन किया। नियमों में सच्चाई को छिपाया गया है। सच्चाई यह है कि उस व्यक्ति ने खुद अपनी पहचान बताने से इनकार करके बैठक के रास्ते में बाधा पैदा की और बाद में दूतावास की छवि खराब करने के

ईरान-अमेरिका युद्धविराम : शांति वार्ता की मेज पर लौट सकते हैं दोनों देश, इस्लामाबाद में सुरक्षा सख्त

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी तनाव को रोकना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब युद्धविराम को अनिश्चित काल के लिए बंद दिया है। ट्रंप ने यह फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फॉर्सेज फौलड मार्शल आसिम मुनिर के अनुरोध पर लिया है। युद्धविराम के बाद शांति के लिए नया रास्ता खुला है। इसी सिलसिले में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ईरानी राजदूत रजा अमीरी मोघदाम से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र की स्थिति और शांति प्रयासों पर लंबी चर्चा की।

राजनयिक मेल-मिलाप का दौर: इससे पहले ईरानी राजदूत ने गृह मंत्री मोहम्मिन तक्वी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने कूटनीति के जरिए तनाव कम करने पर जोर दिया। इसी बीच, पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से बात की। दोनों नेताओं ने विवादों को बातचीत से सुलझाने का समर्थन किया।

इशाक डार ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट से भी मुलाकात की। जेन मैरियट ने वार्ता कराने में पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तान के शांति प्रयासों का पूरा समर्थन किया।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के रेंड जेन में सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। इस इलाके में सरकारी इमारतें और दफ्तर मौजूद हैं। रेंड जेन को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है।



गौण खनिज पट्टों पर ‘स्टार रेटिंग’ प्रणाली लागू करने बहरी में बैठक आयोजित

मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारीविकास मिश्रा के निर्देशन में गौण खनिज उत्खनन पट्टों पर ‘स्टार रेटिंग’ प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 23 अप्रैल 2026 को बहरी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिहावलराजेश शुक्ला की अध्यक्षता एवं खनिज अधिकारीकपिल पुनि शुक्ला की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में बहरी उपखंड क्षेत्र के संचालित उत्खनन पट्टाधारक, उनके प्रतिनिधि तथा प्रभारी खनिज निरीक्षकदेवेन्द्र महोबे एवं खनिज निरीक्षकरजत गौतम उपस्थित रहे। बैठक में खनिज अधिकारी द्वारा पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से ‘स्टार रेटिंग’ प्रणाली एवं खनिज नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि खनन कार्यों का



मूल्यांकन चार प्रमुख मानकों के आधार पर किया जाएगा, जिनमें सुनियोजित खनन (25 प्रतिशत), पर्यावरण संरक्षण (30 प्रतिशत), श्रमिकों का स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण (10 प्रतिशत) तथा खनन संचालन एवं खनिज मूल्य संवर्धन (35 प्रतिशत) शामिल हैं। इन मानकों के आधार पर पट्टाधारकों के कार्यों की

गुणवत्ता एवं अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। अनुविभागीय अधिकारिराजेश शुक्ला ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी पट्टाधारक शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी समय-सीमा के भीतर विभागीय पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खनन की गई जानकारी का



सत्यापन जिला स्तर पर किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। बैठक के अंत में उपस्थित पट्टाधारकों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन करते हुए ‘स्टार रेटिंग’ प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने की सहमति व्यक्त की गई तथा इसे पारदर्शी एवं व्यवस्थित खनन की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया गया।

विद्यालयों में कैंप लगाकर विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनवायें : प्रभारी कलेक्टर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। नागरिकों को आधार सेवाओं का सुलभ एवं त्वरित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक प्रभारी कलेक्टर मती सपना त्रिपाठी की अध्यक्षता में बाणसागर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रभारी कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी विद्यालयों में विशेष कैंप आयोजित कर विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के आधार निर्माण का कार्य बड़ी संख्या में लंबित है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आधार कार्ड शासकीय योजनाओं, छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य है, इसलिए विद्यालय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कर शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनवाने की कार्यवाही की जाए। साथ ही 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं अन्य नागरिकों के आधार पंजीयन को भी प्राथमिकता देने के निर्देश



दिए गए। बैठक के दौरान आधार में दर्ज निवास पते को बार-बार बदलने की प्रक्रिया में शिथिलता लाने के संबंध में भी परामर्श दिया गया तथा इस विषय पर राज्य स्तर से मार्गदर्शन जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रभारी कलेक्टर ने आधार सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि नगरीय क्षेत्रों में कम से कम एक बैंक शाखा में आधार केंद्र का संचालन अनिवार्य रूप से किया जाए। तहसील स्तर पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लंबित नामांकन तथा 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकृत करने के निर्देश भी दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को

जिले की सभी आधार मशीनों को तत्काल क्रियाशील कर नियमित सेवाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए, जिससे आधार सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। बैठक में यूआईडीएआई दिल्ली के परियोजना प्रबंधक निकेत दीवान द्वारा आधार प्रणाली से संबंधित तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। जिला ई-प्रबंधक आशीष दुबे ने ऑपरेटरों को सुचारु संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन देते हुए नामांकन प्रक्रिया में त्रुटियों को शून्य रखने तथा नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास नयन सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्र, डीपीसी राजेश तिवारी, ईडिया पोस्ट के अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पोल्ट्री हैचरी निर्माण देरी पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी :संविदाकारों को नोटिस जारी करने के निर्देश



मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। चितरंगी विकासखंड के ग्राम सकेती में निर्माणाधीन पोल्ट्री हैचरी परियोजना का औचक निरीक्षण किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से सीएसआर मद से बन रही इस परियोजना का उद्देश्य जिले में पोल्ट्री उत्पादन बढ़ाना है मौके पर निर्माण कार्य की धीमी गति

देखकर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान, कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री, ईआरईएस से परियोजना की स्वीकृति तिथि और वर्तमान प्रगति की विस्तृत जानकारी मांगी। उन्हें बताया गया कि यह कार्य लगभग दो साल पहले स्वीकृत हुआ था, जबकि अनुबंध के अनुसार इसे 12



महीने के भीतर पूरा किया जाना था इस पर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इतनी देरी अस्वीकार्य है। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में लगे दोनों संविदाकारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। इसके अतिरिक्त अब तक किए गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता

जांच के लिए एक समिति गठित कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि यदि गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उन्होंने देरी के लिए अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना (पेनल्टी) लगाने के निर्देश भी दिए। इस परियोजना के पूरा होने पर स्व-सहायता समूहों और स्थानीय पोल्ट्री फार्मों को सस्ते दरों पर चूजे उपलब्ध हो सकेंगे। इससे जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

निगम बैठक में कांग्रेस-भाजपा पार्षदों में नोकझोंक स्वच्छता, पेयजल और सफाईकर्मों भर्ती पर तीखी बहस

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। नगर निगम परिषद की बैठक में स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच कई विषयों पर तीखी बहस और नोकझोंक देखने को मिली, जिससे सभागार का माहौल गरमा गया। बैठक में भाजपा पार्षद भारतेंदु पांडे ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस पर कांग्रेस पार्षद अनिल शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में कांग्रेस ने ही सबसे पहले ठोस कदम उठाए थे। उन्होंने देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे



उच्च पदों पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का श्रेय कांग्रेस को दिया इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस जारी रही। स्वच्छता व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 250 सफाई कर्मियों की प्रस्तावित भर्ती अब तक पूरी नहीं हो पाई है जिसके कारण कई बाड़ों में शिबिर और प्रभावी सफाई नहीं हो रही है। पार्षदों ने इस समस्या

के शीघ्र समाधान की मांग की। गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पेयजल संकट पर भी गंभीर चर्चा हुई पार्षदों ने सुझाव दिया कि पानी की आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक के दौरान पार्षद रामगोपाल पाल ने सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह के परिषद में बैठने और बोलने पर आपत्ति जताई।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत शिविर आयोजित, 100 प्रतिभागियों ने लिया लाभ

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिला प्रशासन सीधी एवं मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला सीधी के संयुक्त तत्वावधान में तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेंद्र सिंह सोलंकी के निर्देशन में विकासखंड कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत जुरी में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के महिला एवं पुरुषों को योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता एवं पंजीयन प्रक्रिया के बारे में सरल एवं सहज भाषा में विस्तारपूर्वक समझाया गया, जिससे



लाभार्थियों को योजना से जुड़ने में सुविधा हो सके। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को आवश्यक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण एवं श्रम कार्ड से संबंधित जानकारी भी दी गई।

शिविर में विशेष रूप से यह बताया गया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह योजना सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। शिविर में कुल 100 प्रतिभागियों ने

सहभागिता की, जिनमें से 25 प्रतिभागियों का प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सफलतापूर्वक पंजीयन किया गया। इसके साथ ही 32 महिलाओं के श्रम कार्ड बनाए गए तथा 12 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। यह सुविधा विशेष रूप से उन लाभार्थियों को प्रदान की गई जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। शिविर में स्व-सहायता समूह की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली। महिलाओं ने योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर इसे अपने परिवार और समुदाय के लिए उपयोगी बताया। कार्यक्रम के सफल संचालन में जिला स्तर से जिला प्रबंधक अजय सिंह, विकासखंड प्रबंधक सुरजीत सिंह

तोमर, सुशील त्रिपाठी एवं रामलाल साकेत का विशेष योगदान रहा। इसके अतिरिक्त बैंक सखी, कृषि सखी एवं आजीविका मिशन से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं ने भी सक्रिय सहयोग प्रदान किया। सीएससी सेंटर के माध्यम से दीपक मिश्रा एवं अतुल तिवारी द्वारा प्रतिभागियों का ऑनलाइन पंजीयन कर उन्हें तत्काल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्वरित रही। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने योजना का लाभ प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया इस अवसर पर प्रशासन द्वारा भविष्य में भी ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित करने की बात कही गई।

नेशनल लोक अदालत के संबंध में तहसील न्यायालय चुरहट में प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 09 मई 2026 को जिला न्यायालय सीधी सहित सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में किया जाएगा। उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन, प्रकरणों के चिन्हांकन एवं आवश्यक तैयारियों के संबंध में आज दिनांक 23 अप्रैल 2026 को तहसील न्यायालय चुरहट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी प्रयाग लाल दिनकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायिक



अधिकारीगण, विभिन्न विभागों के पीठासीन अधिकारी, अधिवक्ता सघ के पदाधिकारी तथा अधिवक्तागण उपस्थित रहे। बैठक में आपसी समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित करने, पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराने तथा त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराने के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। प्रधान न्यायाधीश ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि लोक अदालत को अधिक से अधिक जनहितकारी बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई जाए,

जिससे लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण संभव हो सके और आमजन को न्यायालयीन प्रक्रियाओं में राहत प्राप्त हो। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश कुमार शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल त्रिपाठी, सु वर्षा भट्टावी, सु विजया विश्वकर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक सहित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष पाण्डेय, तहसीलदार चुरहट मती सा गौतम, सचिव अधिवक्ता सघ हेमराज पटेल तथा अधिवक्तागण शिवाकांत सिंह पटेल एवं अन्य न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।

होर्मुज आपदा में भारत के लिए अवसर

अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम का विस्तार इस ओर संकेत करता है कि होर्मुज जलमार्ग का खुलना संभव है। वैसे यदि ऐसा हो जाता है तो भी पूर्ववर्ती व्यवस्था की वापसी संभव नहीं लगती। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले खाड़ी क्षेत्र की सामुद्रिक परिवहन व्यवस्था एक नाजुक धारणा पर टिकी थी।

करीब 130 जहाज रोजाना इस 33 किमी चौड़े संकरे जल मार्ग से बिना किसी बाधा के गुजरते थे, पर अब यह धारणा ध्वस्त हो चुकी है।

आर्थिक दृष्टि से इसका अर्थ है कि होर्मुज के पुनः खुलने के बाद भी बीमा लागत ऊंची रह सकती है। शिपिंग कंपनियां इस मार्ग पर निर्भरता घटाने के लिए अपने मार्गों का पुनर्निर्धारण करने में लगी हैं।

खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देश भी समानांतर रूप से खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा के अपने ढांचे की समीक्षा कर रहे हैं। यह केवल भू-राजनीतिक व्यवधान नहीं है। यह वैश्विक व्यापार संरचना का पुनर्संयोजन भी है। इसमें उन मार्गों,

वित्तीय तंत्रों और संस्थागत व्यवस्थाओं का पुनर्गठन हो रहा है, जो तय करते हैं कि सीमा पार वस्तुओं का व्यापार कैसे संचालित होता है।

इस उपरते परिदृश्य में भारत विशिष्ट रूप से सशक्त स्थिति में है। दशकों से भारत को मुख्यतः एक ऊर्जा-निर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया है, जो एक बड़ी हद तक खाड़ी क्षेत्र के तेल

एवं गैस पर निर्भर है।

होर्मुज संकट ने इस सच को भी उजागर किया है कि भारत केवल खरीदार नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता भी है, विशेष रूप से खाद्य और आवश्यक वस्तुओं के मोचे पर। यह शक्ति संतुलन को सूक्ष्म, पर महत्वपूर्ण रूप से बदलने वाला पहलू है।

भारत की शक्ति इस बिंदु में निहित है कि वह

संपादकीय

परंपरा, बाजार और बदलती पहचान

डॉ. प्रियंका सोरभ

भारत की सांस्कृतिक संरचना में त्योहारों का स्थान केवल आनंद और उत्सव तक सीमित नहीं है बल्कि वे समाज की ऐतिहासिक स्मृति, आर्थिक संरचना, प्रकृति के साथ संबंध और मानवीय संवेदनाओं के गहरे ताने-बाने से जुड़े होते हैं। यहाँ त्योहार जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं- खेती, ऋतु परिवर्तन, पारिवारिक संबंध, सामूहिकता और आस्था। लेकिन वर्तमान समय में यह प्रश्न गंभीरता से उठाना जाने लगा है कि क्या हमारे पारंपरिक त्योहार अपनी मूल आत्मा से दूर हो रहे हैं? क्या उन पर एक प्रकार का ‘सांस्कृतिक हमला’ हो रहा है, जो धीरे-धीरे उनकी असल पहचान को बदल रहा है?

सांस्कृतिक हमला शब्द भले आक्रामक प्रतीत होता हो लेकिन इसका आशय किसी एक वर्ग या समूह पर आरोप लगाना नहीं है। यह उस धीमी, सूक्ष्म और कई बार अनदेखी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है, जिसके माध्यम से परंपराएँ अपने मूल सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से हटकर नए अर्थ ग्रहण करने लगती हैं। यह परिवर्तन कभी स्वाभाविक होता है तो कभी सुनियोजित आर्थिक और वैचारिक प्रभावों का परिणाम भी हो सकता है।

भारतीय त्योहारों की जड़ें मुख्यतः कृषि और प्रकृति से जुड़ी रही हैं। देश का अधिकांश समाज सदियों तक कृषि आधारित रहा है इसलिए फसल, मौसम और भूमि के साथ उसका गहरा रिश्ता रहा। फसल कटने की खुशी, नई बुवाई की शुरुआत, वर्षा के आगमन का स्वागत- ये सब त्योहारों के माध्यम से व्यक्त होते थे। इन उत्सवों में किसान केंद्र में होता था क्योंकि वही अन्न का उत्पादक था और वही समाज की जीवन रेखा को बनाए रखता था। ऐसे त्योहारों में आडंबर कम और सहभागिता अधिक होती थी। लोग मिलकर गाते-बजाते, सामूहिक भोज करते और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते थे।

जैसे-जैसे समाज में शहरीकरण बढ़ा, औद्योगिकीकरण हुआ और बाजार की ताकतें मजबूत हुईं, त्योहारों का स्वरूप भी बदलने लगा। अब त्योहारों को केवल सांस्कृतिक या सामाजिक दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक अवसर के रूप में भी देखा जाने लगा। बाजार ने त्योहारों को उपभोग से जोड़ दिया-जहाँ खरीदारी, सजावट और प्रदर्शन को प्रमुखता मिलने लगी। त्योहारों के साथ ‘ऑफर’, ‘डिस्काउंट’ और ‘शुभ खरीदारी’ जैसे विचार जुड़ गए, जिसने उनके मूल स्वरूप को प्रभावित किया।

यह बदलाव केवल बाहरी नहीं है बल्कि मानसिकता में भी आया है। पहले त्योहारों का अर्थ था-मिलना-जुलना, आपसी साझेदारी की भावना और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना। अब कई जगहों पर यह प्रतिस्पर्धा का रूप ले चुका है- किसने कितना खर्च किया, किसने क्या खरीदा, किसका आयोजन कितना भव्य था। इस प्रक्रिया में त्योहारों की आत्मा कहीं पीछे छूटती चली गई।

त्योहारों पर सांस्कृतिक हमले की चर्चा करते समय एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है- लोक परंपराओं का हाशिए पर जाना। भारत में हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट परंपराएँ रही हैं, जो स्थानीय जीवनशैली, भाषा और संसाधनों से जुड़ी होती थीं। लेकिन आज मीडिया और बाजार के प्रभाव में एक प्रकार की सांस्कृतिक एकरूपता देखने को मिल रही है। कुछ खास त्योहारों और उनके खास तरीकों को पूरे देश में मानक बना दिया गया है, जिससे स्थानीय विविधताएँ धीरे-धीरे लुप्त हो रही हैं।

उदाहरण के लिए, कई ऐसे लोकपर्व जो कभी कृषि और ग्रामीण जीवन से जुड़े थे, अब शहरी और धार्मिक व्याख्याओं में बदल गए हैं। उनकी मूल भावना- जो श्रम, प्रकृति और सामूहिकता से जुड़ी थी- अब पौराणिक कथाओं और बाजार-प्रेरित प्रतीकों के पीछे ढकती जा रही है। इससे समाज के उस वर्ग की भूमिका कम होती जा रही है, जो वास्तव में इन त्योहारों की आत्मा रहा है- यानी किसान और श्रमिक।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि हर बदलाव को नकारात्मक दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। संस्कृति का स्वभाव ही परिवर्तनशील होता है। समय के साथ उसमें नए तत्व जुड़ते हैं और यही उसकी जीवंतता का प्रमाण है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है, जब यह परिवर्तन असंतुलित हो जाता है- जब वह समाज के मूल आधार को कमजोर करने लगता है।

योगेश कुमार गोयल

पुस्तकों की महत्ता और इनसे अर्जित ज्ञान के संबंध में सदैव कहा जाता रहा है कि ज्ञान कभी बेकार नहीं होता। पुस्तकें विभिन्न संस्कृतियों, पहचानों और भाषाओं के माध्यम से अपनी विशिष्टताओं को प्रकट करते हुए एक कहानी और एक सामान्य विरासत के आसपास लोगों को एक साथ लाती हैं लेकिन यह चिंताजनक है कि पाठकों में पुस्तकें पढ़ने की आदत निरंतर कम होती जा रही है। लोगों को पुस्तकें पढ़ने, कॉपीराइट कानूनों तथा अन्य उपायों को समझने के लिए प्रोत्साहित करने, लेखकों और पुस्तकों को वैश्विक सम्मान देने तथा पढ़ने की कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को यूनेस्को तथा दुनियाभर के अन्य संबंधित संगठनों द्वारा ‘विश्व पुस्तक दिवस’ मनाया जाता है। ‘विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस’ का औपचारिक शुभारंभ ‘यूनेस्को’ द्वारा 23 अप्रैल 1995 को किया गया था।

यह चिंता का विषय है कि आधुनिकता के दौर में बच्चों के साथ-साथ बड़ों का लगाव भी पुस्तकों के प्रति कम हुआ है। मोबाइल और कम्प्यूटर के जमाने में अब बच्चे जो या बड़े, अधिकांश इन्हीं पर अपना ज्यादातर समय बिताने लगे हैं लेकिन अधिकांश विद्वानों का स्पष्ट मत है कि इंटरनेट या विभिन्न संचार माध्यमों से मिलने वाली जानकारीयों को हमारे मस्तिष्क को चुपचाप ग्रहण करना पड़ता है, जो दिमाग की खुद की कल्पनाशीलता को कुंद कर देते हैं जबकि पुस्तकें पढ़ने के लिए ध्यान, एकाग्रता और मेहनत की आवश्यकता

होती है, जिससे विचारों और भावनाओं के लिए नई रेशनी और प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए जरूरी है कि टीवी या सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से चिपके रहने के बजाय पुस्तकों की दुनिया को जीवन का अभिन्न अंग बनाया जाए ताकि रचनात्मकता का उपयोग करते हुए क्षितिज का विस्तार करने में पुस्तकों की शक्ति का बेहतर उपयोग किया जा सके।

बाल साहित्य और ज्ञानवर्धक पुस्तकों के माध्यम से बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ावा देने और साहित्य के प्रति उनमें आजीवन प्रेम उत्पन्न करने का भी प्रयास किया जाए। जिस समय हमारे आसपास कोई नहीं होता या हम अकेले अथवा उदास हैं, परेशान हैं, ऐसे समय में पुस्तकें ही हमारी सच्ची दोस्त बनकर हमें सहारा देती हैं। हमारे दिलोदिमाग में उमड़ते सवालों का जवाब पाने के लिए पुस्तकों से बेहतर और कोई जरिया नहीं हो सकता।

सभी भारतीय भाषाओं में पुस्तकों को बढ़ावा देने और पढ़ने की संस्कृति विकसित करने की एक पहल के रूप में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रतिवर्ष दिल्ली में भव्य पुस्तक मेले ‘विश्व पुस्तक मेला’ का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के आयोजन लोगों में किताबें पढ़ने की रूचि विकसित करने के साथ-साथ कलम और मुद्रित दुनिया की ताकत को दोहराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि हर साल इतने भव्य और विशाल पुस्तक मेले के सफल आयोजन के बावजूद विशेषकर हिन्दी भाषी पाठकों में पुस्तकें पढ़ने की आदत कम हो रही है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि साल

है।

किसी भी स्कूल का पुस्तकालय बच्चों में पुस्तकों के प्रति प्रेम विकसित करने और उन्हें दुनिया के बारे में अधिक जानने में भी मदद करता है। यही कारण है कि केवल पाठ्य-पुस्तकों को ही बच्चों की समझ को विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। इसीलिए

लापरवाही व उदासीनता साफ झलकती है। हालांकि नई पुस्तकों की खरीद के लिए प्रतिवर्ष लाखों रुपये का बजट आवंटित होता है लेकिन स्कूलों के पुस्तकालयों में रखरखाव के अभाव में पुस्तकों को दीमक चाट रहे हैं। कर्मोबेश ऐसा ही हाल देश के लगभग सभी राज्यों में देखने को मिलता है। स्कूलों में बच्चों के लिए पुस्तकों की उपलब्धता और उनके रखरखाव में लापरवाही के मामलों को गंभीरता से देखने और इसे लेकर कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि स्कूली स्तर पर ही पुस्तकों के प्रति बच्चों का आकर्षण कम न होने पाए।

पुस्तकों की महत्ता को परिभाषित करते हुए अमेरिकी इतिहासकार व लेखक बारबरा डब्ल्यू तुचमन का कहना था कि पुस्तकें सभ्यता की वाहक हैं, जिनके बिना इतिहास मौन है, साहित्य गूंगा है, विज्ञान अंगण है, विचार और अटकलें स्थिर हैं। पुस्तकों की महत्ता और इनसे अर्जित ज्ञान के संबंध में सदैव कहा जाता रहा है कि ज्ञान कभी बेकार नहीं होता और पुस्तकें विभिन्न संस्कृतियों, पहचानों और भाषाओं के माध्यम से अपनी विशिष्टताओं को प्रकट करते हुए एक कहानी और एक सामान्य विरासत के आसपास लोगों को एक साथ लाती हैं। पुस्तकें ज्ञान एवं नैतिकता की सदैववाहक, अखण्ड सम्पत्ति, भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्कृति हेतु एक खिड़की तथा चर्चा हेतु औजार का काम करती हैं तथा भौतिक वैभव के रूप में देखी जाती हैं। अच्छी पुस्तकें बच्चों और युवा पीढ़ी को ज्ञानवान, संस्कारित और चरित्रवान बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाती हैं।

भारत को गोली का सही ज़बाब देना चाहिए

संजय गोस्वामी

शनिवार 18 अप्रैल 26 को होरमुज जलडमरूमध्य में भारत के डझे वाले दो जहाजों पर हुई फायरिंग ने ईरान की सत्ता संरचना में बढ़ती दरार को उजागर कर दिया है। यह फायरिंग इस बात को लेकर हुई भ्रम के कारण हुई कि शनिवार को होरमुज जलडमरूमध्य खुला था या नहीं। जहाँ एक विपट्ट ईरानी अधिकारी ने कहा कि सभी जहाज होरमुज जलडमरूमध्य से गुजर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे ईरान के इस्लामिक रिवाज़ेशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ समन्वय करें, वहीं इसके विदेश मंत्री, अब्बास अराघची ने कहा कि फ़ारस की खाड़ी में यह संकरा रास्ता खुला है, क्योंकि लेबनान में इराक़ल-हिज़्बुल्ला युद्ध के लिए संघर्ष-विराम समझौते पर सहमति बन गई थी। भारत

को नेवी शिप भेज कर इसका करारा जबाब देना चाहिए भारत 140 करोड़ लोगों का एक लोकतान्त्रिक देश है और भारत ऐसा देश है जो गोली का जबाब गोली से देना जानता है भारत के लोग कहीं भी हो अगर हमला हुआ है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए ईरान में सत्ता संघर्ष हो या कुछ भी ऐ एक आतंकवादी घटना है शिप पर भारत का तिरंगा होना यदि इसे शक्ति से नहीं लिया गया तो आतंकी का हौसला बढ़ेगा और दुनिया में इसे मज़ाक बनाया जाएगा जिससे भारत की छवि धूमिल होगी जब ईरान की नेवी को अमेरिका के हमले से बचाने के लिए कोच्ची में अपना नेवी शिप भेज कर अमेरिका को अपनी ताकत का अहसास करा सकता है तो ऐसा हमला बर्दास्त नहीं है चाहे कोई भी हो भारत को इसका करारा जबाब देना चाहिए हम

भगवान राम के मार्गदर्शन पर चलने वाले मान और मर्यादा से रहने वाला शांति प्रिय देश है तो हमें अपने लोगों की रक्षा का पूर्ण अधिकार है भारत को इसे गंभीरता से लेकर जबाबी कार्यवाही करना चाहिए अमेरिका क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ऐ दो देशों का अंदरूनी मामला है इसमें भारत का कोई रोल नहीं है भारत एक शांतिप्रिय देश है और भारत माँ की रक्षा के लिए मर मिटने वाला देश है ऐ हमला बिस्कुल जायज नहीं है इसपर भारत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए ईरान की आबादी 9 करोड़ है और भारत की आबादी 140 करोड़ है इसे यदि हल्के में लिया गया तो परोसी दुश्मन मुक्त मज़ाक उड़ा सकता है क्योंकि उसके जहाज आ रहे हैं हम अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर हैं आतंकी हमला बर्दास्त नहीं है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक की विफलता, राष्ट्र निर्माण को ठेस

डॉ. पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

भारत के भविष्य के खिलाफ विपक्षी राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा अपराध कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों द्वारा संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) को विफल करके प्रदर्शित किया गया असंवैधानिक, अनियंत्रित और महिला विरोधी रवैया है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत को आंतरिक और बाह्य, दोनों मोर्चों पर लड़ना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ कम्युनिस्ट चीन और पश्चिमी जगत की गहरी बाजारवादी ताकतें भारत को अस्थिर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। दूसरा मोर्चा उन आंतरिक विरोधियों का है जो भारत में अशांति फैलाने और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। दोनों ही शत्रुओं को यह जानना चाहिए कि भारत ऐसे सशक्त व्यक्तित्वों को जन्म देता है जो समाज में योगदान देते हैं और राष्ट्र की महानता को पुनर्स्थापित करने में सहायक होते हैं। न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी अनेक अवसरों पर दुश्ता का परिचय देते हुए यह सिद्ध किया है कि भारत को पराजित नहीं किया जा सकता।

रानी अहिल्यादेवी होलकर: भारतीय इतिहास में उनका एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि उनकी शासन शैली प्रशासनिक और सैन्य कोशल के साथ-साथ सौम्य शक्ति (पूरे भारत में सनातन धर्म और सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति सम्मान) पर

भी बल देती है। समय के साथ इतिहास के उन पन्नों में भी महिलाओं के साहस और करुणा की कहानियाँ मिलती हैं जो समय के साथ लुप्त हो गए हैं। फिर भी, उन्होंने हमारी राष्ट्र माता की सेवा करने के अपने प्रयासों में दृढ़ता दिखाई और उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। रानी देवी अहिल्याबाई होलकर को राजमाता के समान एक महान नेता और वीर योद्धा माना जाता है। उनकी अनेक उपलब्धियों से कई पीढ़ियों की महिलाएं प्रेरित हुई हैं, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में प्रचलित लिंगभेद की मजबूत रूढ़ियों और धारणाओं को तोड़ा। एक ऐसी महिला के बारे में सोचिए, जिसने युद्ध में अपने पति को खोने के कुछ वर्षों बाद अपनी इकलौती सहयोगी को भी खो दिया। कई सम्राट युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उनके बीच भी प्रतिद्वंद्वी थे। वह भयभीत नहीं हुईं लेकिन जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो बहुत शत्रुता का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की ने उन्हें ‘दार्शनिक रानी’ का नाम दिया था। निम्न रानियों के लंबे इतिहास वाले देश में देवी अहिल्याबाई होलकर का असाधारण 30 वर्षीय शासनकाल अद्वितीय है, जिसने अमिट छाप छोड़ी और प्रेरणा का स्रोत बना। तमाम मुश्किलों के बावजूद, अपने छोटे से जीवनकाल में सनातन धर्म का विस्तार करके उन्होंने हिंदुत्व के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया, जिसे आज के हर भारतीय को बेहतर भारत और विश्व के लिए अपनाना चाहिए। अरविंद जावलेकर की पुस्तक ‘लोकमाता अहिल्याबाई’

के अनुसार, अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई होलकर ने अपनी सारी संपत्ति भारत भर के मंदिरों के निर्माण, जीर्णोद्धार, नवीनीकरण और रखरखाव में लगा दी थी। हिंदुत्व की प्रतीक अहिल्यादेवी ने धर्म के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक उन्नति को भी बढ़ावा दिया।

शासन और प्रशासन: अहिल्याबाई अपने निष्पक्ष और कुशल शासन के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखी और जनता एवं धर्म के कल्याण को प्राथमिकता दी।

1. अवसररचना विकास: उन्होंने कई अवसररचना संबंधी पहल शुरू कीं जिनसे व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिला, जैसे सिंचाई प्रणाली और सड़कें।

2. संस्कृति का संरक्षण: मंदिरों का निर्माण: एक धर्मनिष्ठ हिंदू होने के नाते, अहिल्याबाई ने पूरे भारत में कई मंदिरों के निर्माण का आदेश दिया। कलाओं को प्रोत्साहन: उन्होंने कवियों, कलाकारों और शिक्षाविदों को सहयोग देकर सांस्कृतिक पुनरुद्धार में योगदान दिया। उनका दरबार कला और साहित्य का केंद्र बन गया।

3. समाज में सुधार: महिलाओं का समर्थन: अहिल्याबाई ने महिलाओं के कल्याण और अधिकारों के लिए सघर्ष किया। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के कई प्रयासों का समर्थन किया और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। परोपकारी कार्य: वे अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थीं, उन्होंने कई सामाजिक कार्यों

का प्रायोजन किया और अकाल के दौरान सहायता प्रदान की।

4. सैन्य रक्षात्मक रणनीतियों में नेतृत्व: अहिल्याबाई शांतिप्रिय नेता थीं, लेकिन वे सैन्य नेतृत्व में भी सक्षम थीं। उन्होंने अपने राज्य को आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखी।

5. धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न समुदायों में एकता: अहिल्याबाई ने धार्मिक सहिष्णुता का अभ्यास और समर्थन करके अपने राज्य के विभिन्न समुदायों में एकता को बढ़ावा दिया, हालांकि उन्होंने सनातन धर्म और महान संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करने वालों पर आक्रमण किया।

6. विरासत का स्थायी प्रभाव: उन्हें भारतीय इतिहास में एक आदर्श माना जाता है और उनकी उपलब्धियों ने एक अमिट विरासत छोड़ी है। पूरे भारत में उनकी प्रतिमाएं और स्मारक हैं। ये प्रतिमाएं और स्मारक उनके बलिदानों और उनके द्वारा प्रतिपादित साहस और एकता की याद दिलाते हैं। यह राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की अवधारणा है जो राष्ट्र के प्रति गौरव और वर्तमान राजनीतिक आकांक्षाओं को दर्शाती है।

इसके अतिरिक्त, यह जनता को उस समय की घटनाओं और आज भी उनके महत्व के बारे में जानकारी देती है। यह स्थानीय पहचान और रीति-रिवाजों के साथ घनिष्ठ संबंध को प्रोत्साहित करती है। स्मारकों के माध्यम से देशभक्ति की भावना और उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साझा

प्रतिबद्धता जागृत होती है जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। नए स्मारकों में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण सहित आधुनिक मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

महिलाओं ने समाज और राष्ट्र की रक्षा करने में अनेक अवसरों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। संसद में महिलाओं का अनुपात अपेक्षा से काफी कम होने पर मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 33% करने का प्रयास किया; हालांकि, वंशवादी राजनीतिक दलों की मानसिकता अपने ही परिवार की महिलाओं की रक्षा करने की है, जबकि वे आम महिलाओं को दी जा रही शक्ति को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। परिणामस्वरूप, उन्होंने विधेयक को पारित होने से रोक दिया। जब तक इस विधेयक पर पुनर्विचार करके इसे लागू नहीं किया जाता, तब तक महिलाएं आगामी चुनावों में सभी विपक्षी दलों से निश्चित रूप से बदला लेंगी।

तीन विधेयकों को लेकर बनी अस्पष्टता पर स्पष्टीकरण: ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’, जिसे अक्सर महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, कहला है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। यदि सरकार जनगणना और उसके बाद परिसीमन का इंतजार करती तो महिलाएं 2029 के आम चुनाव में 33% आरक्षण का लाभ नहीं उठा पातीं, क्योंकि जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया में समय लगता है।

सांसद ज्योत्सना महंत की अध्यक्षता में ‘दिशा’ बैठक सम्पन्न, योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा



मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। समग्र विकास, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की

महत्वपूर्ण बैठक जिला पंचायत कोरिया के मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कौरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने की जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार



से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में सांसद महंत ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया

कि योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचे। भोषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए सांसद ने सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था

सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए इसके लिए पहले से तैयारी और वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके साथ ही बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायतों की जांच करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए गए। टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवाओं और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। सांसद महंत ने बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता व्यक्त करते हुए हेलमेट अनिवार्यता लागू करने, राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतक लगाने तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में ‘मोर

गांव-मोर पानी’ अभियान के तहत जल संरक्षण कार्यों की सराहना की गई। मनरेगा के माध्यम से किए जा रहे कार्यों से जल संकट में कमी आई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। वहीं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की सराहना की गई। ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं से महिलाओं की आय में वृद्धि हो रही है। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और उनके उत्पादों के बेहतर विपणन की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 79 प्रतिशत आवास पूर्ण होने की जानकारी दी गई शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया।

चाइल्ड हेल्थलाइन 1098 की बड़ी सफलता, जिले में बाल विवाह समय रहते रोके गए

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ प्रशासन ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। चाइल्ड हेल्थलाइन 1098 पर प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम कोडांगी, ग्राम पंचायत केलुआ और ग्राम पंचायत दुगला में होने वाले तीन बाल विवाहों को समय रहते रोक दिया गया, जिससे नाबालिगों का भविष्य सुरक्षित हो सका। सूचना मिलते ही कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर जिला प्रशासन हरकत में आया। जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा संयुक्त टीम का गठन किया गया। इस टीम में ब्लॉक परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्थलाइन, थाना केल्हारी और थाना खड़गावां की पुलिस टीम, विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य, सरपंच तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल थे। संयुक्त टीम ने तत्काल तीनों स्थानों पर

पहुंचकर बाल विवाह की प्रक्रिया को रुकवाया और संबंधित परिवारों को समझाइश दी। अधिकारियों ने मौके पर ही बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि यह एक गंभीर अपराध है जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बालक के लिए 21 वर्ष और बालिका के लिए 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करना पूर्णतः गैरकानूनी है। इस तरह के विवाह में शामिल किसी भी व्यक्ति-जैसे पंडित, पुरोहित, टेंट संचालक, रिसेंदार या अन्य सहयोगी-पर 2 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। कार्रवाई के दौरान संबंधित मामलों में पंचनामा और प्रतिवेदन भी तैयार किया गया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने में सहयोग करें और ऐसी किसी भी सूचना को तत्काल टोल फ्री नंबर 1098 पर साझा करें।

मनेंद्रगढ़ का JOS बना प्रदेश का रोल मॉडल, पूरे छत्तीसगढ़ में होगा विस्तार

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले से शुरू हुआ अभिनव स्वच्छता अभियान ‘जर्नी ऑफ सैनिटेशन हाइजीन JOS अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक मिसाल बन गया है। स्वच्छता के साथ रोजगार को जोड़ने वाले इस मॉडल को राज्य स्तर पर आयोजित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की अपेक्ष समिति की बैठक में प्रदेशभर में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव विकास शील द्वारा दिए गए इस निर्देश से स्पष्ट है कि यह नवाचार अब पूरे राज्य में विस्तार पाएगा।

यह अभियान 5 जनवरी 2026 को खड़गावां में प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा प्रारंभ किया गया था अल्प समय में ही इसने उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए जनआंदोलन का रूप



ले लिया है। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के नेतृत्व में इस योजना का जिले के तीनों जनपदों में सुदृढ़ क्रियान्वयन किया गया। अभियान के अंतर्गत संस्थागत, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ही स्वच्छता को जन-जन से जोड़ा गया है। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए एक सशक्त मॉडल विकसित किया गया है, जो आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बन रहा है। जिला समन्वयक राजेश जैन के अनुसार स्वच्छता प्रहरियों द्वारा अब तक लगभग

200 यूनिट शौचालयों की सफाई की जा चुकी है जिससे करीब 60 हजार रुपये की आय अर्जित हुई है। यह पहल दर्शाती है कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। अभियान के तहत शौचालयों की केवल सफाई ही नहीं, बल्कि उनकी मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। JOSअभियान ने यह साबित किया है कि नवाचार, जनभागीदारी और सशक्त नेतृत्व के माध्यम से स्वच्छता के साथ रोजगार और सामाजिक-आर्थिक विकास को नई दिशा दी जा सकती है।

स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है। इस योजना के अंतर्गत प्रति यूनिट मात्र 200 रुपये में गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराई जा रही है जिससे आम नागरिकों को सुलभ सुविधा मिल रही है। योजना के सफल संचालन के लिए शिक्षा, पंचायत, महिला एवं बाल विकास तथा आदिवासी विकास विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक संस्थानों में नियमित साफ-सफाई से जागरूकता भी बढ़ी है। जिले की यह पहल अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। JOSअभियान ने यह साबित किया है कि नवाचार, जनभागीदारी और सशक्त नेतृत्व के माध्यम से स्वच्छता के साथ रोजगार और सामाजिक-आर्थिक विकास को नई दिशा दी जा सकती है।

प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता स्वीकृत

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था के तहत जिले में चार मामलों में राहत राशि स्वीकृत की गई है। यह सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई है जिसका उद्देश्य आपदा की कठिन घड़ी में प्रभावित परिवारों को संबल देना है। जारी आदेश के अनुसार तहसील नागपुर के ग्राम बरकेला निवासी सरिता की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर उनके वारिस जगरनाथ सिंह को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील

खड़गावां के ग्राम जर्गंधा निवासी फुलकुंवर की कुएं में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस धर्मपाल सिंह को 4 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त तहसील खड़गावां के ही ग्राम बेलकामार निवासी अजय कुमार की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस दीपक कुमार सिंह को भी 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। वहीं तहसील केल्हारी के ग्राम मुसरा निवासी गीता की नाले में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस संतलाल को 4 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह सहायता राशि प्राकृतिक आपदा राहत मद के अंतर्गत प्रदान की जा रही है, जिससे प्रभावित परिवारों को

तत्काल आर्थिक सहायता मिल सके और वे संकट की इस घड़ी से उबर सकें। सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच एवं आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही सहायता स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 के मुख्य शीर्ष 2245 (प्राकृतिक आपदा राहत) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में वहन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने बताया कि शासन द्वारा आपदा प्रभावितों के लिए निरंतर राहत उपाय किए जा रहे हैं और भविष्य में भी पात्र हितग्राहियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से स्पष्ट है कि शासन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनशील है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कूटी-ट्रैक्टर की टक्कर में युवक की मौत :ग्रामीणों ने चक्काजाम कर ब्रेकर बनाने की मांग की

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। देहात थाना क्षेत्र में पिपरसमा अनाज मंडी के सामने गुरुवार को स्कूटी और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में 25 वर्षीय युवक अंकेश धाकड़ की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर ब्रेकर बनाने की मांग की। मृतक अंकेश धाकड़ (25), निवासी ऊंची बरोद, अपने मामा के गांव पिपरसमा से वापस लौट रहा था इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हुआ बताया जा रहा है कि स्कूटी और सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच जोरदार टक्कर हुई टक्कर इतनी तेज थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हादसे की वजह ट्रैक्टर चालक की लापरवाही बताई जा रही है हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की

जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और मामा पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। युवक की मौत से सभी में आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया उन्होंने मंडी मार्ग पर ब्रेकर बनाने की मांग उठाई ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोकें जा सकें। चक्का जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई मंडी आने-जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहन काफी देर तक फंसे रहे। सूचना मिलने पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाइश देकर ग्रामीणों को शांत कराया और जाम को हटवाकर यातायात सामान्य कराया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।

धान के लिए हरी खाद सर्वोत्तम विकल्प, कृषि विभाग का विशेष अभियान शुरू



मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में धान उत्पादन बढ़ाने एवं मृदा उर्वरता सुधारने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन के लिए हरी खाद और जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर हरी खाद अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विभाग के अनुसार रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग से मिट्टी में जैविक तत्वों

और लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आ रही है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है और फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए हरी खाद एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प के रूप में सामने आई है। जिले के अधिकांश किसान रोपा पद्धति से धान की खेती करते हैं। ऐसे में रोपाई से पहले खेतों में ढ़ैचा, सन और अन्य शीघ्र बढ़ने वाली दलहनी फसलों की बुवाई कर उन्हें उचित अवस्था में मिट्टी में मिला

दिया जाता है। इससे मृदा में जैविक पदार्थों की वृद्धि होती है तथा वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साथ ही फॉस्फोरस और पोटाश को उपलब्धता भी बढ़ती है। विशेषज्ञों के मुताबिक ढ़ैचा हरी खाद के रूप में अत्यंत उपयोगी है, जिससे प्रति हेक्टेयर लगभग 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त हो सकती है। इसकी बुवाई खेती शुरू होने से 35 से 45 दिन पहले की जाती है और 2 से 3 फुट ऊंचाई होने पर इसे खेत में पलट दिया जाता है। एक सप्ताह के भीतर यह सड़-गलकर प्राकृतिक खाद में बदल जाती है जिससे फसल को आवश्यक पोषण मिलता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। इस अभियान के अंतर्गत जिले में कुल 176 हेक्टेयर क्षेत्र में हरी खाद के उपयोग का लक्ष्य रखा गया है।

माचिस गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान खाक

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। व्यापार विहार स्थित एक माचिस गोदाम में आज सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपये का माचिस और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही नगर निगम और फायर ब्रिगेड की दमकल गाड़ियों मौके पर पहुंचीं। दूसरी घटना सरकारंछा थाना क्षेत्र के अशोक नगर में बुधवार की देर रात दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई जिसमें सारा सामान जल गया। नगर निगम के अपर आयुक्त खर्वांची कुम्हार ने बताया कि आग बुझाने के लिए व्यापार विहार के गोदाम की दीवार तोड़नी पड़ी। आग को फैलने से रोकने के लिए निगम के



एक्सीवेटर और स्काई लिफ्ट का उपयोग किया गया। उन्होंने बताया कि दूसरी मंजिल पर आग बुझाने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके कारण एक्सीवेटर से दीवार तोड़कर आग पर काबू पाया गया। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट दीपांशु नाथ ने बताया कि व्यापार विहार में माचिस और पान मसाला के सामानों की दुकान में सुबह करीब 4 बजे लगी आग पर काबू पा लिया गया है।

OPS में पूर्व सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता :हाईकोर्ट ने खारिज की शासन की अपील, शिक्षकों के पेंशन का रास्ता साफ

मीडिया ऑडीटर, छत्तीसगढ़ (निप्र)। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने एक शिक्षक की याचिका पर राज्य शासन की अपील को निरस्त कर दिया है। साथ ही कहा है कि शिक्षकर्म एलबी की पूर्व सेवा गणना के आधार पर पेंशन के प्रकरणों का निर्धारण किया जाए। OPS कोर्ट ने स्पष्ट कहा है में पूर्व सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब राज्य शासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। दरअसल, चिरमिरी नगर निगम



में पदस्थ शिक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संविलियन से पूर्व की सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि

संविलियन के बाद भी उनकी पूर्व सेवा को पेंशन गणना में नहीं जोड़ा जा रहा है जो उनके साथ अन्याय है। इस मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार

को निर्देश दिया था, वह पूर्व सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने पर विचार करे। इसके लिए सरकार को 120 दिनों का समय भी दिया गया था। हालांकि इस निर्देश पर

अमल करने के बजाय राज्य सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील की थी। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान शिक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल भी पक्षकार के रूप में शामिल रहे। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई। राज्य सरकार ने अपने पक्ष में शर्तों का हवाला देते हुए कहा कि संविलियन के समय जो शर्तें तय की गई थीं उसी के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जाना चाहिए कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि जब संविलियन के दौरान पूर्व सेवा

की गणना को मान्यता दी गई है, तो फिर पुरानी पेंशन योजना में उसे शामिल करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए कोर्ट ने माना कि पूर्व सेवा को नजरअंदाज करना न्यायसंगत नहीं है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ अब इस फैसले के खिलाफ राज्य शासन सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। हालांकि विधि अधिकारियों का कहना है कि फैसले का परीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश में 1.50 लाख से अधिक शिक्षक हैं अगर हाईकोर्ट के आदेश पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाता है तो उन्हें 100% पेंशन देना पड़ेगा।

नर्मदापुरम में 43.2 डिग्री पहुंचा पारा, सड़कों पर सन्नाटा हिल स्टेशन पचमढ़ी में 12 डिग्री का अंतर होने से गर्मी से राहत



मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम और खजुराहो में भीषण गर्मी का दौर जारी है। दिन के साथ रातें भी गर्म होती जा रही हैं, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही। बुधवार को अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री दर्ज हुआ, जो पिछले 24 घंटे में 0.2 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री रहा। दोपहर के समय गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम शुष्क रहने से लू जैसे हालात बन रहे हैं और बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक वी.एस. यादव के अनुसार, अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। बादल हटने से अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होगी और गर्म हवाएं चलेगीं। रात का तापमान भी सामान्य से अधिक बना रहेगा। पिछले चार दिनों से बादल छाए रहने के कारण रात का तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे उमस और गर्मी दोनों का असर महसूस हो रहा है।

पचमढ़ी में राहत, 12 डिग्री कम तापमान: हिल स्टेशन पचमढ़ी में नर्मदापुरम की तुलना में करीब 12 डिग्री कम तापमान दर्ज किया गया। यहां बुधवार को अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री रहा, जो एक दिन पहले 32.8 डिग्री था। पचमढ़ी में रात का तापमान भी नर्मदापुरम की तुलना में 13-14 डिग्री कम है, जिससे वहां लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल रही है।

फंदा बना रही थी महिला, पुलिस ने तोड़ा दरवाजा सागर में 30 वर्षीय महिला सुसाइड करने वाली थी सूचना पर चंद मिनटों में पहुंची पुलिस



मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के धर्माश्री इलाके में बुधवार को 30 वर्षीय एक महिला ने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही डायल-112 और मोतीनगर थाना पुलिस ने चंद मिनटों में मौके पर पहुंचकर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा और फंदा लगा रही महिला की जान बचा ली। पुलिस ने महिला को सुरक्षित बाहर निकालकर समझाइश देकर शांत करा दिया है और मामले में आगे की जांच के लिए उसके बयान दर्ज किए हैं।

कंट्रोल रूम को मिली थी सूचना, चंद मिनटों में पहुंची पुलिस: पुलिस के अनुसार, बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में फोन पर सूचना मिली थी कि धर्माश्री इलाके में रहने वाले अनिल की 30 वर्षीय पत्नी रानी ने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया है और वह फंदा लगाकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। सूचना मिलते ही तत्काल डायल-112 और मोतीनगर थाना पुलिस को मौके पर भेजा गया। पुलिस चंद मिनटों में ही अनिल के घर पहुंच गई, जहां उन्होंने देखा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था।

खिड़की से झांका तो फंदा लगा रही थी रानी: पुलिस टीम ने जब खिड़की से झांकाकर देखा तो रानी फंदा लगा रही थी। यह देखते ही मौके पर पहुंचे एसआई नरवध सिंह और पायलट साजिद खान ने तुरंत पड़ोसियों की मदद ली और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। पुलिसकर्मियों ने तुरंत रानी को पकड़ लिया और फंदा लगाने से रोककर उसकी जान बचा ली। इसके बाद पुलिसकर्मि महिला को पकड़कर बाहर लाए और उसे समझाइश देकर शांत कराया।

छतरपुर में ब्रेक लगते ही गिरे बाराती, ड्राइवर की पिटाई वीडियो में मारपीट कैद, हदसे को लापरवाही मानकर भीड़ ने चालक को पीटा



मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को पिकअप वाहन ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग ड्राइवर के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। यह घटना देवरा और किशनगढ़ के बीच रायपुरा जंगल की घाटी में हुई। जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन एक बारात से लौट रहा था। वाहन के अंदर कुछ बाराती बैठे थे, जबकि कई लोग छत पर सवार थे। रास्ते में अचानक मिट्टी का ढेर आ जाने के कारण ड्राइवर ने वाहन को नियंत्रित करने के लिए अचानक ब्रेक लगाए। ब्रेक लगते ही छत पर बैठे दो बाराती संतुलन खोकर नीचे गिर गए। दोनों बारातियों के गिरने के बाद, वहां मौजूद अन्य लोगों ने इसे ड्राइवर की लापरवाही माना। इसके बाद गुस्साए बारातियों ने ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतारा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सामने आया है।

ड्राइवर को भर्ती कराया: मारपीट में ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि उसके पैर में गहरी चोट लगी है। घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। किशनगढ़ थाना प्रभारी कमलजीत मवई ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अचानक ब्रेक लगाने से दो लोग गिर गए थे, जिसके बाद ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मंदसौर स्व-गणना में प्रदेश में नंबर-1 बना पृथ्वी दिवस पर 19 हजार परिवारों ने भरे प्रपत्र जल संरक्षण का संदेश



छतरपुर में एक साथ 6 जगह लगी आग फायर ब्रिगेड खराब होने से काबू पाने में देरी टैंकर बुलाकर बाल्टी से पानी डालाकर बुझाई

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर जिले के गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र में बुधवार को अलग-अलग 6 स्थानों पर आग लगने से हड़कंप मच गया। शिवपुरा, बैदार, बारी, मुहारी, बड़ी नरवा और बाघराजन क्षेत्रों में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। कई जगह खेतों और आसपास के इलाकों में आग तेजी से फैलती रही, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही गढ़ीमलहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

20 दिनों से फायर ब्रिगेड खराब पड़ी: टीआई रीता सिंह ने नगर परिषद को फायर ब्रिगेड के लिए सूचना दी, लेकिन नगर परिषद की फायर ब्रिगेड पिछले 15-20 दिनों से खराब पड़ी होने



के कारण मौके पर नहीं पहुंच सकी। ऐसे में हालात और भी गंभीर हो गए। स्थिति को संभालने के लिए टीआई रीता सिंह ने महाराजपुर, नौगांव और छतरपुर से फायर ब्रिगेड बुलाने के प्रयास किए। वहीं बड़ी बाघराजन के पास

मोहारी हार क्षेत्र में करीब 20 एकड़ खेत में भीषण आग लगने की सूचना पर वे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और खुद आग बुझाने में जुट गईं।

बाल्टियों और पाइप से बुझाई आग: स्थानीय स्तर पर

संसाधनों की भारी कमी देखने को मिली। जब पानी का टैंकर मौके पर पहुंचा तो उसमें पंप की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में पुलिस और ग्रामीणों ने पाइप लगाकर और बाल्टियों के जरिए पानी भर-भरकर आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान टीआई रीता सिंह खुद भी आग बुझाने नजर आईं।

आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि वह बाढ़ के पानी की तरह आगे बढ़ती जा रही थी, जिससे उसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो रहा था। ग्रामीणों और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद कई जगह आग पर आंशिक काबू पाया जा सका। इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में फायर ब्रिगेड जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर दिया है।

खरगोन में 40 पार तापमान, दोपहर में लू जैसे हालात 10 दिन से 40-41 डिग्री पार 70 लाख मिर्च पौधों को बचाने कर रहे स्पे

मीडिया ऑडीटर, खरगोन (निप्र)। खरगोन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जिससे दोपहर 1 बजे के बाद लू जैसे हालात बन रहे हैं। भीषण गर्मी का असर जनजीवन के साथ खेती पर भी साफ दिखाई दे रहा है। गर्मी से बचाव के लिए किसान खेतों में मिर्च के पौधों पर पानी का स्प्रे कर रहे हैं और स्लाइडिंग नेट का उपयोग कर रहे हैं, ताकि तापमान को नियंत्रित रखा जा सके। बामखल के उन्नत किसान विजय यादव ने बताया कि वे पानी का छिड़काव कर करीब 70 लाख मिर्च के पौधों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नेट हाउस में सुबह-शाम स्प्रे किया जा रहा है। मिर्च की फसल के लिए 20 से 27 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है, जबकि वर्तमान में तापमान इससे कहीं अधिक है। स्लाइडिंग नेट करीब 50% तक गर्मी को रोकने में मदद कर रहे हैं। जिले में करीब 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मिर्च की



रोपाई होती है। यहां की मिर्च निमाड़-मालवा के साथ महाराष्ट्र के कई शहरों में भी भेजी जाती है। इसके लिए पहले से ऑर्डर बुक किए जाते हैं।

पिछले 10 दिनों से 40-41 डिग्री तापमान: पिछले 10 दिनों से जिले में तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच बना हुआ है। पिछले दो दिनों से बादल छाने के कारण रात में भी उमस बढ़ गई है और

न्यूनतम तापमान 22-23 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा और गर्मी और बढ़ सकती है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि वे दोपहर में बिना टोपी या गमछे के धूप में बाहर न निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।

रायसेन के धनोरा में नरवाई की आग गांव तक पहुंची बिजली की चिंगारी से भड़कीग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभालकर पाया काबू



मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। रायसेन के धनोरा गांव में गुरुवार दोपहर नरवाई में लगी आग

ने विकराल रूप ले लिया। यह आग बिजली की चिंगारी से भड़की और तेज हवा के कारण तेजी से

फैलते हुए गांव तक पहुंच गई। आग फैलने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल फायर

ब्रिगेड और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन समय पर कोई सहायता नहीं पहुंची। इसके बाद गांव के समाजसेवी मनोहर मेहरा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने की जिम्मेदारी संभाली। ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों में कल्टीवेटर लगाकर खेतों की जुताई की, ताकि आग की रफ्तार को रोका जा सके। कई ग्रामीणों ने अपने घरों से पानी की मोटर और जनरेटर निकालकर आग बुझाने में सहयोग किया। ग्रामीणों ने दूर-दूर से पानी लाकर सामूहिक प्रयासों से आग पर काबू पाया। शाम करीब 6 बजे तक आग पर नियंत्रण पा लिया गया। इस दौरान हरे-भरे पेड़ झुलस गए और किसानों के आंगन में रखी कटी हुई गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा। आग बुझाने के दौरान एक किसान झुलस गया, जिसने जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दमोह के पुराने थाना परिसर में आग जलशुदा मिनी बस मैजिक, ट्रैक्टर और मिक्सचर मशीन जलकर खाक

मीडिया ऑडीटर, दमोह (निप्र)। दमोह जिले के मड़ियादो स्थित पुराने थाना परिसर में आज गुरुवार सुबह करीब 10 बजे अचानक आग लग गई। घटना में पुलिस अभिरक्षा में रखे चार जलशुदा वाहन आग की चपेट में आ गए और जलकर खाक हो गए। आग से प्रभावित वाहनों में एक जब्त मिनी बस, एक मैजिक गाड़ी, एक ट्रैक्टर और एक मिक्सचर मशीन शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें उठती देख तुरंत थाना प्रभारी प्रीति पांडे को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, जिसके बाद हटा से फायर ब्रिगेड वाहन बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। हालांकि, यह अंदिशा बताया जा रहा है कि पुराने थाना परिसर के आसपास पड़े सूखे पत्तों से आग शुरू हुई होगी, जो धीरे-धीरे वाहनों तक फैल गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे अन्य वाहन आग की चपेट में आने से बच गए। स्थानीय लोगों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से आग को भीषण रूप लेने से रोका जा सका।



उधना-दुर्गापुर स्पेशल ट्रेन इटारसी होकर चलेगी यात्रियों की सुविधा के लिए 26 अप्रैल से 2-2 ट्रिप संचालित होगी

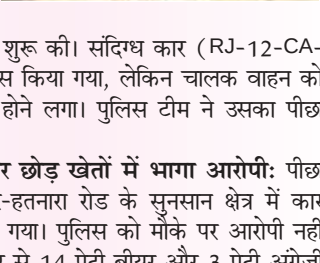


इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 09176 दुर्गापुर-उधना स्पेशल ट्रेन 27 और 28 अप्रैल 2024 को दुर्गापुर से रात 11:50 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन सतना 4:50 बजे, कटनी 6:45 बजे और जबलपुर रात 9:00 बजे पहुंचेगी। ट्रेन इटारसी मध्दरात्रि 12:30 बजे पहुंचकर अगले दिन दोपहर 1:30 बजे उधना पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन में कुल 17 कोच शामिल होंगे। इनमें 5 द्वितीय

चेयरकार, 10 सामान्य श्रेणी के कोच, 1 जनरेटर कार और 1 एसएलआरडी कोच लगाए जाएंगे, जिससे विभिन्न वर्गों के यात्रियों को यात्रा का विकल्प मिलेगा। यह ट्रेन नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल और अंडाल जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी।

राजस्थान पारसिंग कार से पकड़ी 1.80 लाख की शराब रतलाम पुलिस को देख भगाई पुलिस ने पीछा किया तो कार छोड़ कर भाग गए

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। रतलाम के सैलाना थाना पुलिस ने राजस्थान पारसिंग कार से अवैध रूप से लाई जा रही करीब 1.80 लाख रुपए की शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान 17 पेटी बीयर और अंग्रेजी शराब ब्रामद की गई। धामनोद चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर आनंद बागवान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ग्रे रंग की स्वीफ्ट कार में अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने रतलाम-बांसवाड़ा रोड के बोदिना फटा क्षेत्र में चेकिंग शुरू की। संदिग्ध कार (RJ-12-CA-9823) को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन को तेज गति से भगाकर फरार होने लगा। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया।



सुनसान इलाके में कार छोड़ खेतों में भागा आरोपी: पीछा करने पर आरोपी भैसाडाबर-हतनारा रोड के सुनसान क्षेत्र में कार छोड़कर खेतों की ओर भाग गया। पुलिस को मौके पर आरोपी नहीं मिला। तलाशी के दौरान कार से 14 पेटी बीयर और 3 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने वाहन सहित शराब जब्त कर ली है।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फरार चालक की तलाश जारी है।

क्या भारत में फैंस नहीं देख पाएंगे फुटबॉल विश्व कप? प्रसारण अधिकार अब तक नहीं बिके, वजह चौंकाने वाली



फुटबॉल विश्व कप 2026 के भारत में ब्रॉडकास्ट राइट्स अभी तक नहीं बिके हैं, जिसकी वजह ऊंची कीमत, कम विज्ञापन रिटर्न और मैचों की असुविधाजनक टाइमिंग है। जियोस्टार और सोनी जैसे बड़े ब्रॉडकास्टर्स फिलहाल इंतजार की रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि टूर्नामेंट से पहले कोई न कोई डील जरूर हो जाएगी।फीफा विश्व कप 2026 को शुरू होने में अब 50 दिन का समय बचा है। इस बड़े टूर्नामेंट के करीब आते ही दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की उत्सुकता बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत में एक बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मेगा इवेंट के ब्रॉडकास्ट राइट्स यानी प्रसारण अधिकार आखिर अब तक क्यों नहीं बिक पाए हैं?फीफा विश्व कप 2026 को शुरू होने में अब 50 दिन का समय बचा है। इस बड़े टूर्नामेंट के करीब आते ही दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की उत्सुकता बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत में एक बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मेगा इवेंट के ब्रॉडकास्ट राइट्स यानी प्रसारण अधिकार आखिर अब तक क्यों नहीं बिक पाए हैं?भारतीय फैंस के लिए चिंता की वजह भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। यूरोपीय लीग्स से लेकर वर्ल्ड कप तक, दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ी है। ऐसे में जब फीफा वर्ल्ड कप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के प्रसारण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, तो यह भारतीय फुटबॉल समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस स्थिति ने उस दौर की याद भी दिला दी है जब इंडियन सुपर लीग के आयोजन को लेकर भी असमंजस पैदा हो गया था, जिससे देश में फुटबॉल कल्चर को झटका लगा था। अगर इस बार भी ब्रॉडकास्ट डील समय पर नहीं होती, तो यह खेल के प्रचार-प्रसार पर असर डाल सकता है। आखिर क्यों अटक हुई है डील? इस पूरे मामले की जड़ में सबसे बड़ा कारण है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की ऊंची कीमत। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फीफा ने भारत के लिए जो कीमत तय की है, वह स्थानीय ब्रॉडकास्टर्स की अपेक्षाओं से काफी ज्यादा है। फीफा ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की कीमत में भारी कटौती करते हुए लगभग 100 मिलियन डॉलर से घटाकर करीब 35-40 मिलियन डॉलर कर दिया है, फिर भी कोई भी ब्रॉडकास्टर डील के लिए आगे नहीं आया है।

दिल्ली की गलतियां अहमदाबाद में नहीं दोहराई जाएंगी

2030 CWG की आयोजन कंपनी में नहीं होंगे आईओए के पदाधिकारी



दिल्ली।अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में विवादों से बचने के लिए मेजबान गुजरात सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) फूक-फूककर कदम रखने जा हैं। आयोजक ऐसी गलतियां नहीं दोहराना चाहते हैं जो 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में विश्वव्यापी किरकिरी का कारण बनी थीं। जिसके चलते 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन कंपनी (ओसी) में आईओए के शीर्ष पदाधिकारियों को शामिल नहीं किए जाने की तैयारी कर ली गई है।ओसी में आईओए पदाधिकारियों की बजाय सीईओ, सीओओ और सीएफओ जैसे पदों पर विशुद्ध पेशेवर विशेषज्ञों को रखा जाएगा। 2010 के खेलों में आयोजन समिति के चेयरमैन तत्कालीन आईओए अध्यक्ष सुरेश कलमाडी थे। इसमें ज्यादातर पदाधिकारी आईओए से ही संबद्ध थे। 2030 के खेलों के आयोजन की निगरानी का मुख्य जिम्मा मंत्रियों के समूह (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) और उससे नीचे खेलों के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) का होगा। ये दोनों ग्रुप, ओसी के साथ मिलकर काम करेंगे।मंत्रियों के समूह में होंगे देश के कद्दावर मंत्री सूत्र बताते हैं कि मंत्रियों के समूह, निदेशक मंडल और ओसी की घोषणा मई माह के अंत या जून माह तक किए जाने की उम्मीद है। मंत्रियों के समूह की संख्या 10 तक होगी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, सांस्कृतिक-पर्यटन मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्य कामों की मंजूरी मंत्रियों का समूह देगा। इसके नीचे निदेशक मंडल होगा जिसमें कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के दो प्रतिनिधि, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया या आईओए के दो प्रतिनिधि, गुजरात सरकार से जुड़े चार प्रतिनिधि, दो देश के नामी खिलाड़ी और दो सदस्य निजी क्षेत्र से होंगे। निदेशक मंडल, ओसी को कार्यों को सुचारु ढंग से पूरा करने का निर्देश देगा और उन पर निगरानी रखेगा। आयोजन कंपनी में होंगे विशुद्ध पेशेवर :2010 में आयोजन समिति बनी थी, लेकिन अब इसे आयोजन कंपनी का नाम दिया गया है। इसमें विशुद्ध पेशेवरों की नियुक्ति होगी। ओसी कमाई और खर्च का लेखा-जोखा रखेगी। राष्ट्रमंडल खेलों की कमाई का मुख्य स्रोत प्रसारण अधिकारी, प्रायोजक और टिकटों से होने वाली कमाई होगी। ओसी इसके लिए पूरी योजना बनाएगी। साथ ही ओसी यात्रा, रहना, खाना, स्थानीय ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा, इवेंट मैनेजमेंट के अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च का भी ब्योरा रखेगी। ओसी पूरी तरह से गैर-लाभकारी कंपनी होगी।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नया विवाद: राजनीति की एंट्री ईरान की जगह इटली को खिलाने की मांग

फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले ईरान की जगह इटली को शामिल करने का सुझाव सामने आने से नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि, फिलहाल ईरान टूर्नामेंट का हिस्सा है और फीफा ने किसी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं। नियमों के चलते इटली की एंट्री मुश्किल नजर आ रही है।फीफा विश्व कप 2026 से पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है। फाइनैशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दूत ने सुझाव दिया है कि टूर्नामेंट में ईरान की जगह इटली को शामिल किया जाए। इस प्रस्ताव ने फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर राजनीति की एंट्री को लेकर बहस तेज कर दी है। दूत ने खुद किया प्रस्ताव का खुलासा:ट्रंप के विशेष दूत पाओलो जाम्पोली ने इस सुझाव की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने जियानी इन्फैन्टिनो के सामने रखा। उन्होंने कहा, 'मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने ट्रंप और (फीफा अध्यक्ष गियानी) इन्फैन्टिनो से सुझाव दिया कि वर्ल्ड कप में ईरान की जगह इटली को शामिल किया जाए। मैं इटली का रहने वाला हूँ और अमेरिका में होने वाले टूर्नामेंट में अज़रूरी को देखना मेरा सपना है। चार खिताब के साथ उनके पास शामिल होने का मजबूत आधार है।'इटली की गैरमौजूदगी भी बनी चर्चा चार बार की वर्ल्ड चैंपियन इटली इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई, जो फुटबॉल जगत के लिए बड़ा झटका रहा। लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप से बाहर रहना इटली जैसी बड़ी टीम के लिए चौंकाने वाला है। इसी वजह से यह प्रस्ताव और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। क्या ईरान खेलेगा वर्ल्ड कप:फिलहाल ईरान टूर्नामेंट का हिस्सा बना हुआ है। टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है और उसके ग्रुप मैच अमेरिका में होने तय हैं। हालांकि, पहले ईरान ने यात्रा और राजनीतिक तनाव को देखते हुए अपने मैच दूसरे देश में कराने की मांग की थी, लेकिन फीफा ने अब तक शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया है। क्या नियमों के तहत संभव है बदलाव:फीफा के नियमों के मुताबिक, अगर कोई टीम टूर्नामेंट से हटती है तो उसकी जगह दूसरी टीम को शामिल किया जा सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। आमतौर पर उसी महाद्वीप (कॉन्फेडरेशन) की टीम को मौका दिया जाता है। ऐसे में अगर ईरान बाहर होता भी है, तो एशियाई टीम को प्राथमिकता मिलने की संभावना ज्यादा है। इस वजह से इटली का शामिल होना फिलहाल बेहद मुश्किल माना जा रहा है।



अभी सिर्फ सुझाव, फैसला बाकी:यह प्रस्ताव अभी केवल एक सुझाव है और इस पर फीफा की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैन्टिनो ने हाल ही में ईरान टीम से मुलाकात के दौरान साफ किया था कि तैयारियां सामान्य रूप से जारी हैं।

एएफसी चैंपियंस लीग टू: कोमन की हैट्रिक की बदौलत अल-नस्र ने अल-अहली को 5-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई



दुबई, एजेंसी। किंग्सले कोमन ने शानदार हैट्रिक लगाई, जिसके चलते अल-नस्र ने बुधवार को अल-अहली एफसी पर 5-1 की शानदार जीत के साथ एएफसी चैंपियंस लीग टू के फाइनल में जगह बनाई। मेहमान टीम की मजबूत शुरुआत के बावजूद, अल-नस्र की आक्रमण क्षमता निर्णायक साबित हुई और उन्होंने शुरुआती झटके से उबरते हुए रियाद में अपने घरेलू प्रशंसकों के सामने एक व्यापक जीत हासिल की। अल-अहली के पास सात मिनट के भीतर बढ़त बनाने का शानदार मौका था, लेकिन जूलियन ड्रैक्सलर की पेनल्टी को गोलकीपर बेंटो क्रेप्सकी ने बचा लिया। हालांकि, कतर की टीम को स्कोर खेलने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि सेकोउ यानसाने ने एक शानदार शॉट को दूर के कोने में

घुमाकर 1-0 की बढ़त दिला दी। अल-नस्र ने लगभग तुरंत ही जवाब दिया। एंजेलो गैब्रियल ने फ्लैक से आगे बढ़ते हुए कोमान को नजदीकी रेंज से बराबरी का गोल करने का मौका दिया, और फिर सादियो माने के साथ शानदार तालमेल बिठाते हुए मेजबान टीम को बढ़त दिलाने में खुद भी सफल रहे। कोमान ने हाफ-टाइम से ठीक पहले एक बार फिर गोल दागा, रक्षात्मक चूक का फायदा उठाते हुए अल-नस्र को हाफ-टाइम तक 3-1 की बढ़त दिला दी और मैच पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया। फ्रांसीसी विंगर ने 64वें मिनट में अपनी हैट्रिक पूरी की, एंजेलो के एक और सटीक पास के बाद उन्होंने शांति से गोल दागा, जो उनके प्रभावशाली व्यक्तिगत प्रदर्शन का चरम था।

ओलिंपिक 2028 में क्रिकेट मुकाबले पोमोना में खेले जाएंगे: स्टेडियम का काम शुरू, 6 टीमों और टी-20 फॉर्मेट में होंगे मुकाबले

साल 2028 में होने वाले लॉस एंजिल्स ओलिंपिक के लिए क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। कैलिफोर्निया के पोमोना में बुधवार को हुए भूमि पूजन के साथ ही क्रिकेट की 128 साल बाद ओलिंपिक में वापसी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।
पोमोना में खेले जाएंगे मैच
सभी मुकाबले लॉस एंजिल्स से लगभग 50 किलोमीटर दूर पोमोना स्थित फेयरफाउंड्स मैदान पर खेले जाएंगे। ओलिंपिक में क्रिकेट

क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक मील का पथर

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह ने इस अवसर को खेल के लिए एक 'बड़ा मील का पथर' बताया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट वैश्विक खेल बनने की दिशा में बड़ी छलांग लगा रहा है। ओलिंपिक का हिस्सा बनना गर्व की बात है और हमें विश्वास है कि यह बेतु खेलों के दौरान केंद्र बिंदु बनेगा और अमेरिका में क्रिकेट की एक स्थायी विरासत छोड़कर जाएगा।

6 टीमों और टी-20 फॉर्मेट में होंगे मुकाबले

लॉस एंजिल्स ओलिंपिक में क्रिकेट एक आधुनिक फॉर्मेट में लौटेगा। इसमें मेस और विमेंस दोनों कैटेगरी के लिए अलग-अलग टी-20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक टूर्नामेंट में 6 टीमों हिस्सा लेंगी। हर टीम को 15 सदस्यीय स्क्वाड की अनुमति होगी। विजेता टीमों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे।
ओलिंपिक से पहले नाइट राइडर्स के मैच होंगे
ओलिंपिक की तैयारियों के रूप में इस फेयरप्लेक्स ग्राउंड्स पर 'मेजर लीग क्रिकेट' के तीन मुकाबले भी खेले जाएंगे। 1 से 5 जुलाई के बीच होने वाले इन मैचों में स्थानीय टीम लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स एक्शन में नजर आएगी। स्ख अमेरिका की प्रमुख प्रोफेशनल टी-20 लीग है।



वोल्वाड ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतकों के मामले में स्मृति और लैनिंग की बराबरी कर ली है



जोहान्सबर्ग, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वाड्ट ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतकों के मामले में भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंशाना और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मेग लैनिंग की बराबरी कर ली है। लौरा ने जोहान्सबर्ग में भारत के खिलाफ अपने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। 22उन्होंने 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 53 गेंदों में 115 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और पांच छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 216.98 रहा। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान के नाम एक टेस्ट शतक, 13 महिला वनडे शतक और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं। भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान, लौरा ने लगातार तीन बार पचास से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 73.33 के औसत और 174.60 के स्ट्राइक रेट से 220 रन शामिल हैं, जिनमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। मैच की बात करें तो, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। हरमनप्रीत (38 गेंदों में 66 रन, सात चौके और तीन छक्के) और शेफाली वर्मा (46 गेंदों में 64 रन, आठ चौके और दो छक्के) के अर्धशतकों की बदौलत भारत ने 20 ओवरों में 192 रन पर 4 विकेट बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए नॉनकुलुलेको म्लाबा (2/31) सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वाड्ट के शतक (53 गेंदों में 115 रन, 14 चौके और पांच छक्के) और सुने लुस के अर्धशतक (42 गेंदों में 64* रन, छह चौके और दो छक्के) की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 21 गेंदें शेष रहते नौ विकेट से शानदार जीत हासिल की।

दूषित पानी की शिकायत पर महापौर ने किया स्थल निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। वार्ड क्रमांक 16 आजाद नगर में दूषित पानी की शिकायत मिलने पर महापौर अजय मिश्रा 'बाबा' ने मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और जल स्रोतों की स्थिति का जायजा लिया तथा स्थानीय नागरिकों से भी चर्चा कर समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण में पाया गया कि वार्ड के कुछ घरों में लोगों द्वारा नाली क्षेत्र में ही बोरिंग कर ली गई है। इससे भू-जल स्तर प्रभावित होने और केंसिंग में लीकेज की समस्या उत्पन्न होने के कारण गंदा पानी एकत्रित हो रहा है जिससे क्षेत्र में दुर्गंध और दूषित जल आपूर्ति की स्थिति



बन रही है। महापौर ने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार की लापरवाही से नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर

प्रभाव पड़ सकता है इसलिए शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने नाली में अवैध रूप से बोरिंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही जल प्रदाय

विभाग को निर्देशित किया गया कि ऐसी शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। महापौर ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रभावित क्षेत्र में टैंकों के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के



निर्देश भी दिए, ताकि नागरिकों को तत्काल राहत मिल सके। उन्होंने सफाई व्यवस्था की भी समीक्षा की और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान

एमआईसी सदस्य रवि तिवारी, कार्यपालन यंत्री सिद्धार्थ सिंह, राजेश सिंह, सहायक यंत्री राजेश मिश्रा, एस.एन. द्विवेदी, उपयंत्री निखिल रजक तथा सीवरेज एवं जल प्रदाय कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आबकारी टीम चाकघाट की लगातार कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले के त्योंथर तहसील अंतर्गत वृत्त चाकघाट आबकारी टीम द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। टीम ने ग्राम कटरा में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध देशी और विदेशी मदिरा जब्त की है। जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल 2026 को आबकारी टीम ने ग्राम कटरा स्थित राजेंद्र जायसवाल के रिहायशी मकान में दबिश दी, जहां से 12 पेटियों में 220 पाव देशी प्लेन मदिरा तथा उत्तर प्रदेश निर्मित 92 पाव ब्लू एंड व्हाइट व्हिस्की बरामद की गई जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 33,060 रुपये बताई गई है। इस कार्रवाई के बाद आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की

धारा 34(1)(क)(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मामले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है जिसकी जांच की जा रही है। सहायक आबकारी आयुक्त रीवा अनिल जैन ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के परिवहन, निर्माण एवं विक्रय के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्थिति में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश्वर सिंह ठाकुर, आबकारी उपनिरीक्षक नेहा प्रजापति, आरक्षक वेदप्रकाश तिवारी, अखिलेश शुक्ला, आशीष गुप्ता, शुभम द्विवेदी तथा नगर सैनिक राजेंद्र मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इटौरा में होटल कल्चर पर सवाल, नियमों को दरकिनार कर संचालित हो रहे होटल

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। शहर के विश्वविद्यालय क्षेत्र इटौरा में इन दिनों होटलों की आड़ में संचालित गतिविधियों को लेकर स्थानीय स्तर पर गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं। कभी शैक्षणिक माहौल और छात्रों की पढ़ाई के लिए पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में अब कथित रूप से होटल कल्चर तेजी से बढ़ रहा है जिससे वातावरण प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई होटल बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहे हैं। इन होटलों के पास न तो कमर्शियल बिल्डिंग की स्वीकृति है, न ही फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम और न ही खाद्य विभाग से आवश्यक अनुमति ली गई है। इसके बावजूद इनका संचालन जारी है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि इन



होटलों में विश्वविद्यालय और आसपास के कॉलेजों के छात्र-छात्राओं की आवाजाही बढ़ गई है। दिन के समय भी युवाओं का यहाँ आना-जाना देखा जा रहा है, जिससे अभिभावकों में चिंता का माहौल है। उनका कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा जाता है लेकिन कुछ छात्र पढ़ाई से भटकते नजर आ रहे हैं, जिससे उनके भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस पूरे मामले में शिक्षा संस्थानों की भूमिका पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यदि विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रबंधन छात्रों की

उपस्थिति और गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखें तो ऐसी स्थितियों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आने से लोगों में असंतोष है। नागरिकों और अभिभावकों ने मांग की है कि इटौरा क्षेत्र में संचालित सभी होटलों की जांच कराई जाए और जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कदम उठाए जाएं। शहरवासियों का कहना है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है। अब यह देखा होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर कब संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करता है और क्षेत्र में अनुशासन एवं शैक्षणिक वातावरण को पुनः स्थापित करता है।



मीडिया ऑडीटर रीवा। (निप्र)। रीवा जिले में अवैध बाक्साइड और बालू, गिट्टी का उत्खनन एवं परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के संरक्षण में और खनिज अधिकारी रीवा दीपमाला तिवारी के सह पर फलफूल रहा है। नदी-पहाड़ से लेकर सरकारी जमीन से खनिज संपदा का दोहन किया जा रहा है और जिम्मेदार आंखें मू्रि बंदे हैं क्योंकि उन्हें जो मंथली नजराना पहुंच रहा है। जिले के तमाम नदियों पहाड़ों को देखा जा सकता है कि किस तरह से खनिज अधिकारी के संरक्षण में पहाड़ों को खोद कर आधा कर दिया गया और टप्पस नदी में 24



घंटे अवैध बालू का उत्खनन हो रहा है। जबकि नियमतः वैध कारोबार परिवहन खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति, वैध खनिज पट्टा और परिवहन पास अनिवार्य है किंतु जमीनी हक्कीकत ठीक उलट है। बिना अनुमति के उत्खनन एवं परिवहन हो रहा है। जब कभी कोई ईमानदार अधिकारी जांच करता है तो कई घंटों बाद फर्जी गयल्टी का कागज दिखाया जाता है जिस कारण शासन को हर माह लाखों का राजस्व हानि हो रही है। जिसे लेकर कंग्रेस पिछड़वर्ग के राष्ट्रीय समन्वयक व किसान नेता कुंवर सिंह पटेल ने रीवा खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके

संरक्षण में ही अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन का खुलेआम कारोबार हो रहा है। खनिज अधिकारी ने लूट की दुकान खोल रखी है। कुंवर सिंह का आरोप है कि जिले का खनिज विभाग अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने में नाकाम है। खनिज माफियाओ पर कार्यवाही नहीं होती बल्कि संरक्षण दिया जा रहा है किसान नेता ने बताया कि सेमरिया, टीकर और महोबा,सुपेदा, बेला, बैजनाथ और भोलगढ़ जैसे इलाकों में खुलेआम बाक्साइड का उत्खनन और हाइवा ट्रक से परिवहन हो रहा है लेकिन कभी कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के संरक्षण में सारे अवैध कार्य हो रहे हैं इस वक्त विजयरघवगढ़ भाजपा विधायक संजय पाठक ने पूरे रीवा जिले में कब्जा कर खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी के मिलीभगत से बाक्साइड का उत्खनन, सेमरिया थाने के पीछे का पूरा पहाड़ बाक्साइड के लिए खोद डाला गया है।

नही? क्योंकि दीपमाला तिवारी पहले कटनी में रह चुकी है और विधायक संजय पाठक से अच्छे संबंध हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब सैया भये कोतवाल तो डर कोहे का। कुंवर सिंह ने कहा कि जिले में परिवहन विभाग के अधिकारी 8 साल से जमे हुए हैं और परिवहन को लूट का अड्डा बना दिये हैं इसीतरह से कई विभागों में कई वर्षों से अधिकारी कर्मचारी एक जगह पदस्थ हैं लेकिन स्थानांतरण नहीं हो रहा है क्योंकि सभी को डिप्टी सीएम का संरक्षण प्राप्त है। किसान नेता ने आरोप लगाया है कि जब से डिप्टी डायरेक्टर दीपमाला तिवारी रीवा आई हैं तब से खनिज विभाग लूट का अड्डा बन गया, जिसकी जांच होना चाहिए। जिले के अतरेला थाना क्षेत्र में अवैध बालू का उत्खनन, बनकुइयां में पत्थर, बाक्साइड, सेमरिया से जैतवार तक बाक्साइड का उत्खनन, सेमरिया थाने के पीछे का पूरा पहाड़ बाक्साइड के लिए खोद डाला गया है।



मीडिया ऑडीटर, जवा, (निप्र)। जिले के जवा तहसील मुख्यालय में बीती रात लगभग 12 बजे के आसपास अज्ञात कारकों से शिवम हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लग गआग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार आग लगने की घटना में पेंट, प्राइमर, सीसीटीवी कैमरे, एलईडी टीवी सहित अन्य हार्डवेयर सामग्री पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके साथ ही पेंट बनाने में उपयोग होने वाली मशीन भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लगभग 6 से 7 लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। दुकान संचालक समयलाल गुप्ता ने बताया कि उन्हें आग लगने की जानकारी देर से मिली। पड़ोसियों के अनुसार रात लगभग 12 बजे दुकान से हल्की दुर्गंध महसूस हुई थी, लेकिन उस समय किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। आग धीरे-धीरे अंदर ही अंदर फैलती रही, जिसके कारण समय पर इसका पता नहीं चल सका। सुबह करीब 6 बजे जब दुकान खोली गई, तब अंदर से धुआं और आग की लपटें निकलती देखी गईं, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना दी गई। तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान पूरी तरह जल चुका था। पीड़ित दुकानदार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग करते हुए कहा है कि आगजनी से उन्हें भारी नुकसान हुआ है।

फोरलेन निर्माण में लापरवाही के आरोप, धूल से इटौरा क्षेत्र में हालात गंभीर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले में रतहरा से चोरहटा तक निर्माणाधीन फोरलेन सड़क को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। निर्माण कार्य कर रही केसीसी कंपनी पर नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों का पालन न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। विशेष रूप से इटौरा विश्वविद्यालय पुल क्षेत्र में धूल और अव्यवस्था के कारण हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार निर्माण स्थल पर अत्यधिक धूल उड़ने से दृश्यता प्रभावित हो रही है जिससे सड़क पर आवागमन जोखिमपूर्ण हो गया है। दिन के समय भी धूल का घना गुबार छा जाने से वाहन चालकों को आगे का रास्ता देखने में कठिनाई होती है जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। लोगों का आरोप है कि निर्माण के दौरान आवश्यक सावधानियां,



जैसे नियमित पानी का छिड़काव और सुरक्षा प्रबंधन, पर्याप्त रूप से नहीं किए जा रहे हैं। विशेष रूप से पुल क्षेत्र में फ्लाई ऐश डाले जाने के दौरान भी धूल नियंत्रण के उपायों की कमी बताई जा रही है। रिहायशी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। घरों में धूल पहुंचने से लोगों को सांस संबंधी परेशानियां हो रही हैं, वहीं बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई

बार शिकायत किए जाने के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने की बात कही जा रही है। वाहन चालकों का कहना है कि अचानक धूल का गुबार उठने से सड़क पर वाहन चलाना जोखिम भरा हो गया है। ऐसे हालात में दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है जिससे लोगों में भय का माहौल है। इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं स्थानीय लोगों ने मांग की है कि निर्माण कार्य की



गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की तत्काल जांच कराई जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और निर्माण कार्य को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं।

कलेक्टर ने किया गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण, छोटे किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश



मीडिया ऑडीटर,मऊरांग (निप्र)। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने सेवा सहकारी समिति पहाड़ी निरपत सिंह स्थित

गेहूं खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण कर उपार्जन व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान

उन्होंने अब तक की गई गेहूं खरीदी, स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया एवं भंडारण व्यवस्था की जानकारी संबंधित अधिकारियों

से प्राप्त की। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित किसानों से भी संवाद किया और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन हर पात्र किसान की उपज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों की समस्याओं और शंकाओं को गंभीरता से सुनते हुए उनका तत्काल समाधान किया। स्लॉट बुकिंग व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पहले छोटे किसानों के स्लॉट बुक किए जाएंगे इसके बाद क्रमशः मध्यम

एवं बड़े किसानों को अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि सभी वर्ग के किसानों को समान अवसर मिल सके और किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो। कलेक्टर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे स्लॉट बुकिंग को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि निर्धारित समय सीमा में सभी पात्र किसानों के गेहूं की खरीदी सुनिश्चित की जाएगी उन्होंने उपार्जन केंद्र में व्यवस्थाओं की और बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए।

एवं बड़े किसानों को अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि सभी वर्ग के किसानों को समान अवसर मिल सके और किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो। कलेक्टर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे स्लॉट बुकिंग को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि निर्धारित समय सीमा में सभी पात्र किसानों के गेहूं की खरीदी सुनिश्चित की जाएगी उन्होंने उपार्जन केंद्र में व्यवस्थाओं की और बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए।

कोर्ट परिसर में मेडिकल, क्लीनिक व दूध दुकान की मांग, अधिवक्ता संघ प्रत्याशी ने कलेक्टर से की पहल



आने वाले लोगों को अक्सर दवा, पानी और बच्चों के लिए दूध जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे समय के साथ-साथ उन्हें काफी असुविधा भी होती है। यदि परिसर में ही मेडिकल, क्लीनिक और दूध-नाश्ते की दुकानें स्थापित की जाती हैं, तो इससे सभी को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख

किया कि वे पूर्व में जिला अधिवक्ता संघ के कोषाध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार रह चुके हैं, जिसमें उन्हें 716 मत प्राप्त हुए थे। इससे पहले ग्रंथपाल पद के चुनाव में उन्हें 600 मत मिले थे। वर्तमान में वे जिला अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। द्विवेदी ने कहा कि न्यायालय परिसर में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार जर्जरित है अत्यंत आवश्यक है, जिससे दूर-दराज से आने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी के मौसम में राहत मिल सके। इस मांग को लेकर अधिवक्ता संघ के कुछ सदस्यों ने भी समर्थन जताया है और इसे एक सकारात्मक एवं जनहितकारी पहल बताया है।